खबर पेज 5 पर

गंभीर समाचार

समय–समाज–संस्कृति

खबर पेज 8 पर

वर्ष -12 | अंक–21 | पाक्षिक समाचार पत्रिका | कोलकाता, शुक्रवार 16 – 31 जनवरी 2026 | मूल्यः 5 रुपये | RNI No.WBHIN/2014/59321, ISSN No. 2456/3005 Kolkata | कुल पृष्ठ – 8

सुविचार

- उम्र थका नहीं सकती ठोकरें गिरा नहीं सकती अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती।
- समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है।

शेरो-शायरी

- मोहब्ब मरने का उसी को देख कर जीते हैं जिस काफ़िर पे दम निकले
- होश वालों को ख़बर क्या बे-ख़ुदी क्या चीज़ है इश्क़ कीजे फिर समझिए ज़िंदगी क्या चीज़ है
- अब के हम बिछड़े तो शायद कभी ख़्वाबों में मिलें जिस तरह सूखे हुए फूल किताबों में मिलें

स्कॉटिश चर्च कॉलेज की एक छात्रा की रहस्यमयी मौत

निज संवाददाता : स्कॉटिश चर्च कॉलेज की एक छात्रा की रहस्यमयी मौत हो गई। मरने वाली छात्रा का नाम ऋषिता बनिक है। ऋषिता बनिक को कॉलेज हॉस्टल से बेहोशी की हालत में आरजी कर हॉस्पिटल ले जाया गया था। वहीं उसकी मौत हो गई। उसकी मौत कैसे हुई, यह अभी साफ नहीं है। बड़तल्ला पुलिस स्टेशन ने पहले ही अननैचुरल डेथ का केस दर्ज कर लिया है और घटना की जांच शुरू कर दी है। शुरुआती अंदाज़ा है कि यह घटना फूड पॉइज़निंग की वजह से हुई होगी। हालांकि, दूसरे पहलुओं की भी जांच की जा रही है।पुलिस सूत्रों के मुताबिक, ऋषिता बनिक स्कॉटिश चर्च कॉलेज की थर्ड ईयर की छात्रा थी। वह त्रिपुरा की रहने वाली थी। वह कोलकाता में कॉलेज के हॉस्टल में पढ़ती थी। स्टूडेंट अचानक हॉस्टल में बीमार पड़ गई। उसके बाद उसे हॉस्टल के सिक रूम में ले जाया गया। वहां से ऋषिता को बेहोशी की हालत में निकाला गया। उसके बाद उसे रात भर आरजी कर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां कॉलेज स्टूडेंट की मौत हो गई। इस घटना को लेकर काफी हलचल थी। बॉडी को पहले ही बरामद कर लिया गया है और ऑटोप्सी के लिए भेज दिया गया है। जांच करने वालों का शुरुआती अंदाज़ा है कि यह घटना फूड पॉइज़निंग की वजह से हुई होगी। हालांकि, जांच करने वाले पूरी रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे हैं।

अमित शाह ने दिया ममता को चैलेंज

बंगाल की सत्ता में आएंगे, सभी भ्रष्ट लोगों को एक-एक करके जेल में डालेंगे

कहा-टीएमसी के कुशासन और तुष्टीकरण का अंत होगा

आनंदपुर घटना को लेकर साधा निशाना

निज संवाददाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आनंदपुर आग की घटना को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधा। शनिवार को शाह ने उत्तर 24 परगना के बैरकपुर आनंदपुरी मैदान में कार्यकर्ताओं के सम्मेलन से शिकायत की कि आनंदपुर में हुई घटना कोई हादसा ही नहीं थी। आग में 25 लोगों की मौत हो गई। 27 लोगों का अभी भी पता नहीं है। गोदाम वेटलैंड पर बना था। इसे बाहर से बंद कर दिया गया था। इस वजह से आग लगने के बाद भी मजदूर बाहर नहीं आ सके। वे अंदर जलकर मर गए। इस आग में ममता के लोग शामिल हैं। अगर ममता सरकार उन्हें छिपाना चाहती है, तो वह ज्यादा समय तक ऐसा नहीं कर पाएगी। क्योंकि अप्रैल के बाद पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में आएगी। और फिर केंद्रीय गृह मंत्री ने दोषियों को जेल भेजने की धमकी दी। ममता को डर है कि भतीजे का नाम सामने आ जाएगा। शाह ने आरोप लगाया कि ममता की सरकार पूरी तरह करप्शन में डूबी हुई है। एक के बाद एक नेता और मंत्री जेल जा रहे हैं। लेकिन फिर ममता उन्हें टिकट देंगी। क्योंकि ममता जानती हैं कि अगर उन्होंने टिकट नहीं दिए, तो वे नेता भतीजा (यानी अभिषेक बनर्जी) के नाम सामने ला देंगे। शाह ने ममता को चैलेंज करते हुए यह भी कहा कि अगर उनमें हिम्मत है, तो तृणमूल उन नेताओं और मंत्रियों को टिकट न दे।

निज संवाददाता : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ''मां, माटी, मानुष'' का नारा, जिसके तहत वे सत्ता में आई थीं, अब अर्थहीन हो गया है क्योंकि राज्य में तीनों ही असुरक्षित हैं। उत्तर 24 परगना में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करते हुए शाह ने पश्चिम बंगाल में बिगड़ती कानून व्यवस्था, उनके गुट और घुसपैठियों द्वारा की जा रही जबरन वसूली और दमनकारी नियंत्रण, और राष्ट्रीय सुरक्षा और चुनावी निष्पक्षता पर इसके प्रभाव को लेकर ममता सरकार की आलोचना की। अमित शाह ने कहा कि ममता दीदी की सरकार के राज्य में, जो मां, माटी, मानुष के नारे के साथ सत्ता में आई थी, आज तीनों ही - मां, माटी और मानुष- असुरक्षित हैं। मां असुरक्षित है; महिलाओं की सुरक्षा की कोई ठोस गारंटी नहीं है। मानुष ममता के गुट से परेशान है, और माटी घुसपैठियों के चंगुल में फंस गई है। रामायण से तुलना करते हुए शाह ने कहा कि जिस प्रकार रावण स्वयं को अजेय समझता था, उसी प्रकार बनर्जी को भी हार के लिए तैयार रहना चाहिए।

उन्होंने दावा किया कि राज्य में भाजपा का वोट शेयर 50 प्रतिशत से अधिक होगा और पार्टी भारी बहुमत से अगली सरकार बनाएगी। अमित शाह ने कहा कि जब भगवान श्री राम ने रामसेतु बनाया था, तब रावण ने भी यही सोचा था कि इस धरती पर मुझे कौन हरा सकता है? ममता जी, इस बार सावधान हो जाइए, भाजपा का वोट शेयर अब 50 प्रतिशत से अधिक होने वाला है और हमारी सरकार भारी बहुमत से बनेगी।

वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर अमित शाह ने कहा कि एक ओर सरकार ने इस पर्व को मनाने का निर्णय लिया है, वहीं दूसरी ओर ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के स्वार्थ में वंदे मातरम का विरोध कर रही हैं। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध नहीं कर रही हैं, बल्कि बंगाल की पहचान और भारत के गौरव का विरोध कर रही हैं। अमित शाह ने कहा कि इस साल वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ है... प्रधानमंत्री मोदी सरकार ने पूरे देश में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाने का फैसला किया है... लेकिन विडंबना देखिए। जब बंगाल में उत्पन्न और बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम पर संसद में चर्चा हुई, तो ममता बनर्जी के सांसदों ने चर्चा का विरोध किया... क्या बंगाल की धरती वंदे मातरम के इस विरोध को सहन कर सकती है?... हमें बंगाल के हर व्यक्ति तक, हर मतदाता तक, हर नागरिक तक यह संदेश पहुंचाना होगा कि ममता बनर्जी और टीएमसी वोट बैंक की राजनीति और घुसपैठियों को खुश करने के लिए वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं।

भारतीय तटरक्षक बल का 50वां स्थापना दिवस

पांच दशक में बना समुद्र का शक्तिशाली प्रहरी

निज संवाददाता : भारतीय तटरक्षक बल (इंडियन कोस्ट गार्ड) 1 फरवरी को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाने जा रहा है। साल 1977 में शुरू हुआ यह बल आज देश की समुद्री सुरक्षा की सबसे अहम ताकत है। शुरुआत में तटरक्षक बल के पास सिर्फ 7 जहाज़ थे, लेकिन आज इसके बेड़े में 155 जहाज़ और 80 विमान शामिल हैं।भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना 1 फरवरी 1977 को भारत के समुद्री इलाकों की सुरक्षा के लिए की गई थी। इसका उद्देश्य तटों की रक्षा करना, समुद्र में कानून व्यवस्था बनाए रखना, तस्करी और अवैध गतिविधियों को रोकना, समुद्र में फंसे लोगों की जान बचाना और समुद्री पर्यावरण की सुरक्षा करना है।तटरक्षक बल भारत के 2.01 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) और करीब 11,098 किलोमीटर लंबी तटरेखा की निगरानी करता है। आधुनिक जहाज़ों, विमानों और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणालियों के जरिए आईसीजी हर समय समुद्र पर नजर रखता है।समुद्र में किसी भी तरह की आपदा हो, भारतीय तटरक्षक बल सबसे पहले मदद के लिए पहुंचता है। अब तक आईसीजी 11,800 से ज्यादा लोगों की जान बचा चुका है। तूफान, नाव दुर्घटना, मेडिकल इमरजेंसी या जहाज़ खराब होने जैसी स्थितियों में तटरक्षक बल की भूमिका बेहद अहम रही है।भारतीय तटरक्षक बल ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय नौसेना के साथ मिलकर अहम भूमिका निभाई। इसके अलावा लक्षद्वीप और केरल तट के पास हुई कई बड़ी समुद्री घटनाओं में त्वरित और प्रभावी कार्रवाई कर जान-माल की रक्षा की।

सरकार के लक्ष्य के अनुसार, 2030 तक भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में 200 जहाज़ और 100 विमान होंगे। इससे आईसीजी दुनिया के प्रमुख तटरक्षक बलों में शामिल हो जाएगा। तटरक्षक बल आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के तहत स्वदेशी जहाज़, विमान, हेलिकॉप्टर और निगरानी उपकरण शामिल कर रहा है। साथ ही जवानों के लिए बेहतर सुविधाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी जोर दिया जा रहा है।भारतीय तटरक्षक बल महिलाओं को समुद्री, हवाई और तटीय सभी भूमिकाओं में बराबरी का मौका देता है।

कोलकाता में गंगा किनारे 42 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पैसेंजर टर्मिनल

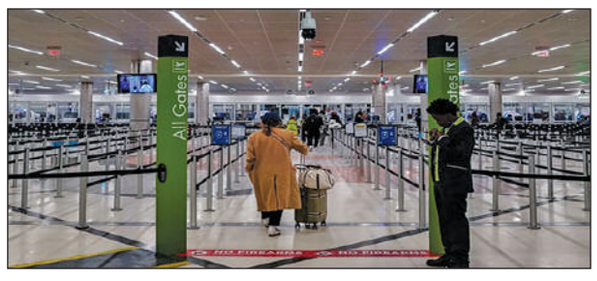

निज संवाददाता : कोलकाता, हावड़ा और आस-पास के इलाकों की सड़कों पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ रहा है। आम आदमी ट्रैफिक जाम से परेशान है। इसके विकल्प के तौर पर वॉटर ट्रांसपोर्ट पर ज़ोर दिया जा रहा है। और इसी मकसद से राज्य सरकार गंगा किनारे स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बनाने की योजना बना रही है। सूत्रों के मुताबिक, स्टेट-ऑफ-द-आर्ट पैसेंजर टर्मिनल की शुरुआती लागत 42.6 करोड़ रुपये आंकी गई है। इसके लिए टेंडर मंगाने का प्रोसेस शुरू हो चुका है। फिर नियमों के मुताबिक टर्मिनल बनाने का काम दिया जाएगा। पूरे मामले की देखरेख वेस्ट बंगाल ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड करेगा। हालांकि, पैसेंजर टर्मिनल की सही जगह के बारे में साफ तौर पर नहीं बताया गया है। सूत्रों के मुताबिक, पैसेंजर टर्मिनल कोलकाता मेट्रोपॉलिटन एरिया के तहत हुगली नदी के किनारे बनाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित पैसेंजर टर्मिनल कोलकाता या हावड़ा में आमतौर पर मिलने वाले फेरी घाटों से कहीं ज़्यादा मॉडर्न होगा। यात्रियों के चढ़ने और उतरने के लिए खास इंतज़ाम होंगे। ज़्यादा यात्रियों के आने पर भी भीड़ न हो, इसका खास ध्यान रखा जाएगा। एक खास टिकट काउंटर होगा। एक बड़ा वेटिंग एरिया बनाया जाएगा ताकि यात्री लॉन्च या फेरी का इंतज़ार कर सकें। सूत्रों के मुताबिक, कुल मिलाकर एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बनाया जाएगा।

संबंधित सूत्रों के मुताबिक, अभी कोलकाता और हावड़ा और आस-पास के इलाकों में ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ गया है। इसमें मीटिंग और जुलूस भी जुड़ गए हैं। इस वजह से लोगों को लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसा रहना पड़ता है। उस समस्या से छुटकारा पाने के लिए राज्य सरकार वॉटर ट्रांसपोर्ट पर ज़ोर दे रही है। इसी वजह से टर्मिनल और जेटी समेत कई इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से व्यवस्थित किया जा रहा है। भविष्य में वॉटरवेज़ ट्रांसपोर्ट का एक अहम ज़रिया बनेंगे। राज्य ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारियों के मुताबिक, वॉटर ट्रांसपोर्ट से खर्च कम होने के साथ-साथ एनवायरनमेंटल पॉल्यूशन को भी कंट्रोल किया जा सकता है।

इस वजह से, भविष्य में वॉटरवेज़ ट्रांसपोर्ट का एक ज़रूरी ज़रिया बन जाएगा। ऐसे में, राज्य सरकार भविष्य को देखते हुए वॉटर ट्रांसपोर्ट को प्रायोरिटी दे रही है। इसके साथ ही, अधिकारियों ने बताया कि राज्य सरकार लंबे समय से हुगली नदी का ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के तौर पर अच्छा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रही है। उसी कोशिश के तहत, हुगली नदी के किनारे एक स्टेट-ऑफ़-द-आर्ट पैसेंजर टर्मिनल बनाया जा रहा है।

पीयूष पांडे बनाए गए बंगाल की राजनीति के लिए अगले तीन महीने होंगे बड़े निर्णायक कार्यवाहक डीजीपी

निज संवाददाता : भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) के वरिष्ठ अधिकारी पीयूष पांडे को शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) का कार्यवाहक नियुक्त किया गया। यह नियुक्ति मौजूदा डीजीपी राजीव कुमार के सेवानिवृत्त होने के कारण की गई है। जारी आदेश के अनुसार, 1993 बैच के अधिकारी पीयूष पांडे अगले आदेश तक कार्यभार संभालेंगे। बता दें कि 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार 31 जनवरी को सेवानिवृत्त हो गए हैं। इसलिए पीयूष पांडे को पश्चिम बंगाल का कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। विवाद यहीं पर है, क्योंकि पश्चिम बंगाल के अगले डीजीपी का चयन गृह विभाग के अधीन गठित समिति (सीएटी) द्वारा किया जाना है। पश्चिम बंगाल सरकार को डीजीपी पद के लिए 3 आईपीएस अधिकारियों के नाम भेजने को कहा गया था। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस संबंध में 8 नाम भेजे हैं। इनमें पीयूष पांडे का नाम था या नहीं, यह अभी भी एक प्रश्नचिह्न है। चूंकि पश्चिम बंगाल सरकार ने अभी तक यह तय नहीं किया है कि बंगाल का डीजीपी कौन होगा और राजीव कुमार का कार्यकाल खत्म हो चुका है, इसलिए पीयूष पांडे को कार्यवाहक डीजीपी नियुक्त किया गया है। कार्यवाहक डीजीपी की नियुक्ति के आदेश में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों के तबादलों की भी सूचना दी गई है, जिनमें कोलकाता के पुलिस आयुक्त मनोज कुमार वर्मा को पश्चिम बंगाल में सुरक्षा निदेशक के पद पर तैनात किया गया है, जबकि दक्षिण बंगाल के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजी) और पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) सुप्रतिम सरकार उनकी जगह लेंगे।

- बीजेपी ने बना ली 'परिवर्तन' की रणनीति
- तय करेंगे ममता बनर्जी का भविष्य

निज संवाददाता : बंगाल की राजनीति के लिए आने वाले तीन महीने बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। पिछले डेढ दशक से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को चुनौती देने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी ने अगले तीन महीनों के लिए अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप दे दिया है। बीजेपी ने फरवरी महीने में पार्टी संगठन और बूथ की मजबूती का टार्गेट रखा है। बीजेपी ने अपने प्रदेश संगठन को कहा है कि फरवरी महीने में संगठन की मजबूती के लिए किया गया काम बीजेपी को सत्ता में लाने की वजह बनेगा। मार्च में बीजेपी ने पूरे प्रदेश में परिवर्तन यात्राएं निकालने की तैयारी की है, ताकि जनता को टीएससी सरकार की नाकामियों बताकर बीजेपी खुद को तृणमूल कांग्रेस के विकल्प के रूप में पेश कर सके। बीजेपी का प्रदेश संगठन राज्य में जारी एसआईआर पर विशेष ध्यान दे रहा है। दरअसल पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के विशेष पुनरीक्षण अभियान के बाद 14 फरवरी को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन होगा, जिसके बाद पार्टी बूथ स्तर पर मतदाता सूचियों की समीक्षा करेगी। फिलहाल राज्य में करीब 81 हजार पोलिंग बूथ हैं, लेकिन चुनाव आयोग के नए मानकों के अनुसार प्रति बूथ अधिकतम 1200 मतदाता होने की सीमा तय की गई है। लिहाजा बूथों की संख्या बढ़कर लगभग एक लाख तक पहुंच सकती है। ऐसे में फरवरी में बीजेपी नई संख्या के अनुसार बूथों की संरचना तैयार करेगी। फरवरी का महीना वैसे भी राज्य में दसवीं और बारहवीं कक्षा की परीक्षाओं के कारण साइलेंट पीरियड माना जाता है। इस दौरान लाउडस्पीकरों पर प्रतिबंध होने के चलते बड़ी रैलियों और राजनीतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होती। बीजेपी इस साइलेंट पीरियड का उपयोग संगठन के ढांचे को मजबूत करने में करेगी। इस फरवरी भर बूथ स्तर पर संगठन को सशक्त करने और प्रचार के पारंपरिक तरीकों पर फोकस किया जाएगा। योजना के मुताबिक फरवरी के साइलेंट पीरियड के खत्म होते ही मार्च में बीजेपी पूरे राज्य में परिवर्तन यात्राएं निकालेगी। इन यात्राओं को राष्ट्रीय स्तर के नेता हरी झंडी दिखाएंगे, जिनमें गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन और यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल हो सकते हैं। राज्य के बड़े बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी, समिक भट्टाचार्य, सुकांत मजूमदार, अग्निमित्रा पॉल, लॉकेट चटर्जी और दिलीप घोष इन यात्राओं का नेतृत्व करेंगे। सभी यात्राओं का समापन कोलकाता में एक विशाल रैली के साथ करने की तैयारी है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित कर सकते हैं। गौरतलब है कि बीजेपी ने संगठनात्मक तौर पर राज्य को छह जोनों में बांटा है। हरेक जोन की जिम्मेदारी बाहर से आए वरिष्ठ नेताओं को सौंपी गई है। साथ ही हर जोन में निगरानी के लिए बड़े नेताओं की तैनाती की गई है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ समन्वय स्थापित करने के साथ ही विधान सभावार भी प्रभारी नियुक्त किए गए हैं। बीजेपी ने राज्य की 162 विधानसभा सीटों पर विशेष फोकस करने का फैसला किया है और सभी 294 सीटों पर चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है। साथ ही तापस रॉय की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय संकल्प पत्र समिति का गठन भी कर दिया गया है। बीजेपी ने चुनाव में हिंदुत्व, महिला सुरक्षा, घुसपैठ और भ्रष्टाचार को प्रमुख मुद्दा बनाने का फैसला किया है। पार्टी सीधे ममता बनर्जी पर व्यक्तिगत हमलों से बचते हुए उनकी सरकार के कामकाज को निशाने पर रखेगी। जनवरी महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राज्य का दौरा किया।

गृह मंत्री अमित शाह ने सांसदों और विधायकों को जनता से संपर्क बढ़ाने के निर्देश दिए थे। अमित शाह के निर्देश के बाद पार्टी ने राज्यभर में डेढ़ हजार से अधिक संपर्क सभाएं आयोजित कीं। इसके साथ ही बीजेपी ने नुक्कड़ सभाओं के जरिए छोटे-छोटे चौक-चौराहों पर अड्डे किए, जिसमें आम लोगों से सीधा संवाद करने के साथ ही टीएमसी सरकार के खिलाफ जनता को अपनी बात रखने का मौका भी दिया गया। पश्चिम बंगाल की विधानसभा का कार्यकाल सात मई को खत्म हो रहा है। राज्य में चुनाव मार्च के अंतिम हफ्ते और अप्रैल के अंतिम हफ्ते के बीच कराए जाने की संभावना है। साल 2021 में आठ चरणों में विधानसभा चुनाव हुए थे, पर इस बार कम चरणों में चुनाव कराए जाने की उम्मीद जताई जा रही है।

एसआईआर को लेकर शिकायत पर सीईसी ज्ञानेश कुमार से मिलेंगी ममता

चुनाव आयोग ने 2 फरवरी का समय दिया

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) को लेकर चल रहे विवाद के बीच सीएम ममता बनर्जी दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त से मुलाकात करेंगी। भारतीय निर्वाचन आयोग ने टीएमसी के प्रतिनिधिमंडल को 2 फरवरी यानी सोमवार शाम करीब 4 बजे निर्वाचन सदन आने का निमंत्रण दिया है। टीएमसी का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए एसआईआर पक्षपातपूर्ण तरीके से किया जा रहा है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी ने बीते 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर कहा था कि पश्चिम बंगाल के करीब 1.5 करोड़ मतदाताओं के दस्तावेजों में तार्किक विसंगतियां पाई गई हैं या उन्हें 2002 के वोटर लिस्ट से नहीं जोड़ा गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग बीजेपी के इशारे पर लोगों के वोट देने के अधिकार छीनने में व्यस्त है। 85 वर्ष से अधिक आयु के मतदाताओं

और दिव्यांगों को अपनी पहचान साबित करने के लिए बुलाया जा रहा है। ऐसे दबाव के कारण तनाव में लोग आत्महत्या कर रहे हैं। टीएमसी का आरोप है कि एसआईआर के बहाने आयोग बंगाल में एनआरसी लागू कर रहा है। इसमें खासकर अल्पसंख्यकों और कमजोर वर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। बता दें कि ममता बनर्जी पहले भी मुख्य चुनाव आयुक्त को एक पत्र लिखकर एसआईआर प्रक्रिया पर विरोध जता चुकी हैं। पश्चिम बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया नवंबर में शुरू हुई थी। इसके बाद से ही राज्य में चुनाव आयोग और सत्ताधारी टीएमसी के बीच तकरार हो रही है। टीएमसी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को अपने सॉफ्टवेयर के गलतियों की लिस्ट प्रकाशित करने का आदेश दिया था। तृणमूल कांग्रेस का आरोप है कि इस प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। वोटरों के नाम में थोड़ी सी भी गड़बड़ी है, उन्हें सुनवाई के लिए बुलाया जा रहा है। इससे खासकर बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी हो रही है।

मालूम हो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी और टीएमसी के नेता मैदान में उतर चुके हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने हाल ही में सिंगूर में एक जनसभा की थी। इसके जवाब में ममता बनर्जी ने बीते बुधवार को उसी स्थान पर रैली की और पीएम मोदी पर सिंगूर में एक भी उद्योग का शिलान्यास न करने का आरोप लगाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सिंगूर में खेती और उद्योग दोनों साथ-साथ फलेंगे-फूलेंगे। उन्होंने कहा कि सिंगूर में अमेजन और फ्लिपकार्ट अपने गोदाम बनाएंगे। साथ ही, एक प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क भी विकसित किया जाएगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा।

2026 की जंग से पहले बंगाल का मूड

- आंकड़ों में तृणमूल कांग्रेस आगे
- मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूती से खड़ी भाजपा

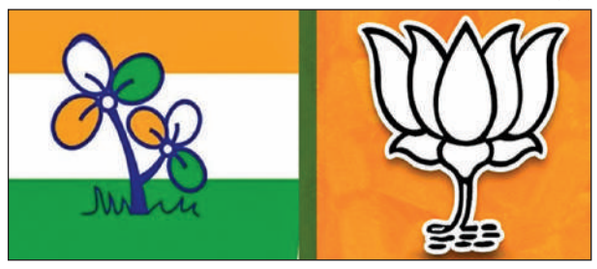

निज संवाददाता : पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की सरगर्मी तेज होने लगी है और इसी बीच एक ताजा प्री-पोल ओपिनियन सर्वे ने राज्य की सियासी तस्वीर को काफी हद तक साफ कर दिया है। विजन ओरिएंटेड लीडरशिप टीम द्वारा किए गए इस व्यापक सर्वे में ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को स्पष्ट बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल के रूप में मजबूती से खड़ी नजर आती है।

सीटों का अनुमान, किसे कितनी बढ़त?

294 सदस्यीय विधानसभा के लिए जारी सीट अनुमान के मुताबिक तृणमूल कांग्रेस को 169 सीटें, भारतीय जनता पार्टी को 114 सीटें और अन्य दल (लेफ्ट फ्रंट, कांग्रेस, ईएसएफ व क्षेत्रीय पार्टियां) को 11 सीटें मिलती दिख रही है। यह सर्वे राज्य की सभी 294 विधानसभा सीटों पर आधारित है, जिसमें बूथ-स्तरीय डेटा, मतदाता रुझान, सामाजिक-क्षेत्रीय समीकरण और स्थानीय राजनीतिक परिस्थितियों का गहन विश्लेषण शामिल है।

क्षेत्रीय समीकरण, कहां किसका पलड़ा भारी?

रिपोर्ट के अनुसार दक्षिण बंगाल, कोलकाता और मध्य क्षेत्रों में तृणमूल कांग्रेस की पकड़ मजबूत बनी हुई है। वहीं उत्तर बंगाल, आदिवासी बहुल इलाकों (झाड़ग्राम, पुरुलिया, बांकुड़ा) और सीमावर्ती क्षेत्रों में भाजपा का प्रभाव बढ़ा है। कई सीटों पर त्रिकोणीय या बहुकोणीय मुकाबले के संकेत भी सामने आए हैं, जो चुनाव को और रोचक बनाते हैं।

क्या होंगे निर्णायक फैक्टर?

सर्वे की प्रमुख बातों में यह साफ उभरकर आया है कि स्थानीय नेतृत्व और बूथ प्रबंधन चुनावी नतीजों में निर्णायक साबित होंगे। मतदाता टर्नआउट और नैरेटिव कंट्रोल आधुनिक चुनावों में जीत-हार की दिशा तय कर रहे हैं। आखिरी चरण की रणनीति कई सीटों पर खेल पलट सकती है। वोल्ट एलएलपी ने यह अध्ययन डेटा आधारित और क्षेत्र विशिष्ट रणनीति के तहत किया है। इसमें प्राथमिक मतदाता सर्वे, बूथ-स्तर पर संगठनात्मक आकलन, पिछले चुनावों के रुझानों का विश्लेषण, रियल-टाइम राजनीतिक फीडबैक शामिल हैं। हालांकि सर्वे में तृणमूल कांग्रेस को बढ़त दिखाई गई है, लेकिन रिपोर्ट यह भी साफ करती है कि पश्चिम बंगाल का 2026 का चुनाव बेहद प्रतिस्पर्धात्मक होगा। क्षेत्रीय समीकरण, मतदाता सहभागिता और अंतिम दौर की रणनीतियां तय करेंगी कि सत्ता की चाबी आखिर किसके हाथ लगेगी। बंगाल की सियासत में फिलहाल एक बात तय है कि मुकाबला दिलचस्प है, और आखिरी फैसला अभी बाकी है। मालूम हो कि वोल्ट एक पेशेवर चुनाव प्रबंधन और राजनीतिक रणनीतिक संस्था है, जो वोटर रिसर्च, डेटा एनालिटिक्स, ग्राउंड ऑपरेशंस और बूथ लेवल निष्पादन में विशेषज्ञता रखती है। इसकी स्थापना राहुल कुमार सिंह ने की है, जो संस्थापक और रणनीतिक नेतृत्वकर्ता हैं। उनके नेतृत्व में संस्था ने खुद को एक अनुशासित, नैतिक और परिणाम-केंद्रित राजनीतिक परामर्श संगठन के रूप में स्थापित किया है।

माकपा के केंद्रीय महिला संगठन के शीर्ष पद पर कनिनिका घोष बोस

- अलग-अलग पदों पर बंगाल लॉबी से आए और कई लोग

निज संवाददाता : कनिनिका घोष बोस को माकपा के महिला संगठन, सारा भारत गणतांत्रिक महिला समिति का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी चुना गया है। कनिनिका माकपा के कोलकाता ज़िले की पार्टी मेंबर हैं। वे अभी पार्टी की राज्य कमेटी में हैं। हाल ही में, कनिनिका हैदराबाद में गणतांत्रिक महिला समिति की जनरल सेक्रेटरी बनीं। पार्टी की बंगाल लॉबी से किसी को ऑल-इंडिया लेवल पर रखना बेशक अहम है। इस राज्य की लीडरशिप पार्टी के छात्र और युवा संगठनों के प्रमुख के तौर पर भी है। बड़ी बात यह कि इस बार, माकपा के एक और बड़े संगठन, महिला समिति के शीर्ष पर एक बंगाली चेहरा पहुंचा है। पीके स्मृति को फिर से

महिला संगठन का अध्यक्ष चुना गया है। तापसी प्रहराज ट्रेज़रर हैं। मालिनी भट्टाचार्य ऑल इंडिया गणतांत्रिक महिला समिति की एडवाइजर हैं। जहांआरा खान, मोनालिसा सिन्हा, अत्रेयी गुहा, रमा विश्वास, देवलीना हेम्ब्रम, दीपू दास, सोमा दास, इशिता मुखर्जी, मणि थापा, परमिता सेन रॉय, सिक्ता जोआर्डर, सुपर्णा बनर्जी को ऑल इंडिया एग्जीक्यूटिव कमेटी में चुना गया। नए चेहरों को लाने की माकपा की पहल संगठन की केंद्रीय कमेटी में साफ दिख रही है। कोलकाता के बेलगछिया इलाके की नेता कनिनिका घोष बोस ने हमेशा लेफ्ट के महिला संगठन के लिए काम किया है। वे कई बार विधानसभा और लोकसभा चुनाव में कैंडिडेट भी रह चुकी हैं। हालांकि वह जीती नहीं हैं, लेकिन कनिनिका हमेशा सक्रिय भूमिका में देखी गई हैं। चाहे विरोध जुलूस हो या पार्टी मीटिंग। संगठन में कनिनिका घोष बोस कोलकाता की नेता के तौर पर काफी पॉपुलर चेहरा हैं। और उसी काम को देखते हुए अब उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर महिला लीडरशिप का टॉप पोजीशन संभाला है। इसके अलावा, संगठन में अलग-अलग पदों पर महिलाओं के एक ग्रुप को जिम्मेदारी दी गई है।

बदल सकती है राज्य कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग की तारीख

निज संवाददाता : राज्य विधानसभा का अंतरिम बजट सत्र कुछ दिनों के लिए टाल दिया गया है। वैसे तो यह सत्र 31 जनवरी को शुरू होना था, लेकिन बाद में इसे बदलकर 3 फरवरी कर दिया गया। प्रशासनिक सूत्रों के मुताबिक, शेड्यूल में इस बदलाव की वजह से राज्य कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग की तारीख बदल सकती है। पहले यह तय हुआ था कि 2 फरवरी को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व में विधानसभा में उनके घर पर राज्य कैबिनेट की स्पेशल मीटिंग होगी। उस मीटिंग में कैबिनेट उनके नेतृत्व में सरकार के अंतरिम बजट को मंज़ूरी देगी। इस बारे में एक नोटिफिकेशन भी जारी किया गया था। लेकिन बदले हुए हालात में, नवान्न सूत्रों के मुताबिक, शेड्यूल बदला जा रहा है।

2 फरवरी से शुरू होगी माध्यमिक परीक्षा

निज संवाददाता : राज्य के स्कूलों में 2 फरवरी से माध्यमिक परीक्षा शुरू होने वाली है। इसे ध्यान में रखते हुए कोलकाता पुलिस ने ट्रैफिक नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। परीक्षा के दिनों में भारी गाड़ियों को कंट्रोल किया जाएगा। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा ने इस बारे में एक नोटिफिकेशन जारी किया है। कोलकाता पुलिस के नोटिफिकेशन के मुताबिक, शहर में माध्यमिक परीक्षा के दिनों में सुबह 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक कोलकाता पुलिस के तहत आने वाले इलाकों में मालवाहक गाड़ियों को चलने की इजाज़त नहीं होगी। ज़रूरी सामान (जैसे एलपीजी, पेट्रोलियम, तेल,

लुब्रिकेंट्स, ऑक्सीजन, दूध, दवाइयां, सब्जियां, फल, मछली) ले जाने वाली भारी गाड़ियों को सुबह 8 बजे तक कोलकाता की सड़कों पर चलने की इजाज़त होगी। जहां माध्यमिक परीक्षा केंद्र हैं, वहां ट्रैफिक कंट्रोल किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर गाड़ियों का रूट डायवर्ट किया जा सकता है। कोलकाता पुलिस ने कहा कि ये नियम भी परीक्षा के लिए जारी किए गए बाकी सभी नियमों के साथ लागू होंगे। मालूम हो कि माध्यमिक परीक्षा 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12 फरवरी को हैं। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बताया कि 2026 के लिए माध्यमिक एडमिट कार्ड बांटने का काम 20 जनवरी को पूरा हो गया है।

यूजीसी के नये नियमों से अगड़े-पिछड़ों में फूट, सियासत भी तेज

अजय कुमार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के एक नए नियम ने उच्च शिक्षा संस्थानों ही नहीं समाज में भी 'आग' लगा दी है। बीजेपी अभी तक जिस हिन्दू समाज को एकजुट करने के लिये बड़े-बड़े कार्यक्रम चला रही थी, सबको एक मंच पर लाने की कोशिश कर रही थी, उसके सामने यूजीसी ने ऐसा 'धर्म संकट' पैदा कर दिया है जिसके एक तरफ खाई तो दूसरी तरफ कुंआ है। हिन्दू समाज अगड़े-पिछड़ो में बंट कर एक-दूसरे के खिलाफ सड़क पर उतर आयें हैं। ऐसे में सरकार समाज के एक वर्ग को साधती है तो दूसरा वर्ग नाराज हो जाता है, दूसरे को साधती है तो पहला नाराज हो जाता है। वैसे तो यूजीसी ने नये नियम बनाते हुए इससे जातिगत भेदभाव रोकने का दावा किया है, लेकिन इसी नियम ने सवर्ण छात्रों के लिए इसे खतरा बताते हुए हिन्दुओं में अगड़े-पिछड़ों के बीच नई दरार पैदा कर दी है। वैसे यह नियम सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बने हैं, लेकिन यह नियम सुप्रीम कोर्ट की मंशा के कितना अनुरूप हैं यह चर्चा का गरमागरम मुद्दा बन गया है। बहरहाल, ऐसा लगता है कि यूजीसी के ये नियम समाजवादी पार्टी को राजनीतिक लाभ दे सकते हैं जबकि भाजपा को नुकसान पहुंचाने की आशंका है। वहीं कुछ बुद्धिजीवी यह भी मानते हैं कि बीजेपी ने दलितों और पिछड़ों की बड़ी आबादी को अपने पक्ष में करने के लिये नये बदलाव किये थे, क्योंकि यह मानकर चला जा रहा था कि सवर्ण मतदाताओं के सामने बीजेपी के अलावा कहीं और जाने का रास्ता नहीं है। उधर, इस मुद्दे पर चल रहे आंदोलन तेज होते जा रहे हैं। वहीं यूजीसी के नये नियम और माघ मेला विवाद के बाद सुर्खियों में आये शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के अपमान को लेकर उत्तर प्रदेश के जिला बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट

अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद तक से त्यागपत्र दे दिया और आंदोलन पर उतर आये।

पहले बात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के उस नियम की जिसे उसने 13 जनवरी 2026 को उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता बढ़ावा देने वाला नया नियम बताते हुए जारी किए, जो 15 जनवरी से सभी मान्यता प्राप्त कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में लागू भी हो गए। इन नियमों का उद्देश्य कैंपसों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ होने वाले कथित भेदभाव को समाप्त करना बताया गया है। हर संस्थान को समान अवसर केंद्र स्थापित करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें समता समिति बनेगी जो शिकायतों का निपटारा करेगी। लेकिन इन नियमों ने सवर्ण छात्रों में भय पैदा कर दिया क्योंकि भेदभाव की परिभाषा में केवल इन्हीं वर्गों को पीड़ित माना गया है, जबकि सवर्णों को संभावित अत्याचारी ठहराया जा सकता है। झूठी शिकायतों पर कोई सजा न होने से दुरुपयोग की आशंका बढ़ गई। सवाल यह है कि यूजीसी के सामने ऐसी क्या आवश्यकता थी इन नियमों की, यह प्रश्न इसलिये उठा क्योंकि पहले से ही भेदभाव रोकने के उपाय मौजूद थे। आलोचकों का कहना है कि ड्राफ्ट में अन्य पिछड़ा वर्ग को शामिल न करने पर आपत्ति हुई तो अंतिम रूप में जोड़ दिया गया, जिससे सामान्य वर्ग के छात्र उच्च कटऑफ तथा पूर्ण शुल्क का बोझ सहते हुए और असुरक्षित हो गए। रोहित वेमुला मामले तथा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के बाद यह कदम उठाया गया, लेकिन इससे हिन्दू समाज में नई फूट पड़ रही है। सवर्ण संगठनों ने इसे सामाजिक तनाव फैलाने वाली साजिश करार दिया। कहां हुई चूक, तो चूक यही है कि नियम एकतरफा बने, सवर्णों के अधिकारों की अनदेखी की गई तथा झूठी शिकायतों पर अंकुश न लगाया। वहीं दूसरी तरफ इसे हिन्दुओं के बीच मतभेद पैदा करने का जिम्मेदार यूजीसी तथा केंद्र सरकार को ठहराया जा रहा है। सवर्ण आर्मी तथा राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना जैसे संगठनों ने आरोप लगाया कि यह हिन्दू एकता तोड़ने का प्रयास है। भाजपा सरकार पर इल्जाम है कि वह पिछड़े वर्गों को साधने के चक्कर में सवर्ण भाइयों को कुर्बान कर रही है। इससे समाज में अगड़े-पिछड़ों का भाईचारा खतरे में पड़ गया।

बात समाजवादी पार्टी की कि जाये तो नये नियम से समाजवादी पार्टी को बड़ा फायदा हो सकता है क्योंकि वह पिछड़े तथा दलित वोटों पर निर्भर है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में सवर्ण असंतोष से भाजपा के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लग सकती है। पार्टी के नेता इसे सामाजिक न्याय का हथियार बना सकते हैं। वहीं भाजपा को भारी नुकसान की संभावना है क्योंकि उसके कई युवा मोर्चा पदाधिकारी तथा सवर्ण नेता इस्तीफा दे चुके हैं। पार्टी को सवर्णों का समर्थन खोने का डर सता रहा है। यह मुद्दा उग्र रूप धारण कर सकता है क्योंकि सोशल मीडिया पर अभियान तेज है तथा सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर हो चुकी है। यदि नियम वापस न हुए तो पूरे देश में आंदोलन फैल सकते हैं।

गौरतलब है कि आंदोलनों की शुरुआत 15 जनवरी के बाद हुई जब सोशल मीडिया पर विरोध शुरू हुआ। लखनऊ के हजरतगंज में राष्ट्रीय हिंदू सनातनी सेना ने विशाल प्रदर्शन किया, जिसमें अध्यक्ष राहुल हिंदू ने इसे काला कानून बताते हुए विधानसभा घेराव की चेतावनी दी। कणनी सेना भी सड़क पर उतर आई। जौनपुर में संगठनों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा। दिल्ली में सवर्ण समाज ने यूजीसी कार्यालय घेराव का ऐलान किया, ठाकुर शिवम सिंह ने इसे एकता के लिए खतरा बताया। बरेली के उप जिलाधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने पद से इस्तीफा दे दिया। भाजपा युवा मोर्चा नोएडा के उपाध्यक्ष राजू पंडित समेत दस पदाधिकारियों ने त्यागपत्र दिए। जयपुर तथा अन्य शहरों में सवर्ण संगठन सड़कों पर उतरे। हैशटैग जैसे नियम वापस लो प्रचारित हो रहे हैं। लखनऊ इकाई से भाजपा नेता भी विरोध में हैं। आंदोलन शांतिपूर्ण रहे लेकिन तनाव बढ़ रहा है। यदि मांगें न मानी गईं तो समाज चरमरा सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर लगाई रोक

- केंद्र को नोटिस जारी, 19 मार्च को अगली सुनवाई
- अगले आदेश तक 2012 वाले नियम रहेंगे लागू

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने) विनियम, 2026 को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। कोर्ट में इन विनियमों को सामान्य वर्गों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण होने के आधार पर चुनौती दी गई है। ऐसे में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगी दी। अब नए आदेश तक 2012 के नियम ही लागू रहेंगे।

केंद्र को नोटिस जारी, 19 मार्च को अगली सुनवाई

सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि नए नियम अस्पष्ट हैं। कोर्ट के कहा कि नए यूजीसी नियमों का दुरुपयोग हो सकता है। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया और यूजीसी के नए नियमों पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने इन रिट याचिकाओं की सुनवाई की। इस दौरान मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि हमें जातिविहीन समाज की ओर बढ़ना चाहिए या हम पीछे जा रह हैं।

जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि क्या हम उल्टी दिशा में जा रहे। जिन्हें सुरक्षा चाहिए, उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। इसी के साथ उन्होंने केंद्र और यूजीसी से जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि एक विशेष कमेटी भी बनाई जा सकती है। इसी के साथ नए नियमों की भाषा को स्पष्ट करने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पर भी जोर दिया।

याचिकाकर्ता के वकील विष्णु शंकर जैन का बयान

इधर, सुप्रीम कोर्ट की ओर से यूजीसी रेगुलेशन 2026 पर रोक लगाने पर एक याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने कहा-आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिट याचिका पर सुनवाई की, जिसमें हाल ही में बनाए गए यूजीसी रेगुलेशन को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी रेगुलेशन पर रोक लगा दी है और उन्हें अभी लागू नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि अगले आदेश तक यूजीसी रेगुलेशन 2012 ही लागू रहेंगे। मामले की अगली सुनवाई 19 मार्च को होगी।

यूजीसी के नए नियमों से देशभर में आक्रोश

दरअसल, यूजीसी रेगुलेशन, 2026 को 23 जनवरी, 2026 को नोटिफाई किया गया था। जिसे लेकर पूरे देश में आक्रोश फैल गया। जिसके बाद इसे कई याचिकाकर्ताओं ने मनमाना, भेदभावपूर्ण और संविधान के साथ-साथ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एक्ट, 1956 का उल्लंघन बताते हुए चुनौती दी। यूजीसी इक्विटी रेगुलेशन के खिलाफ याचिकाएं मृत्युंजय तिवारी, एडवोकेट विनीत जिंदल और राहुल दीवान ने दायर की हैं। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि ये नियम सामान्य वर्गों के खिलाफ भेदभाव को बढ़ावा देते हैं।

कोलकाता में बनेगा नया वॉटर प्रोजेक्ट

- मेयर फिरहाद हकीम ने दिया भरोसा
- 25 साल बाद भी पीने के पानी की कोई दिक्कत नहीं होगी

निज संवाददाता : कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य पूरे राज्य का विकास है। जिलों में सड़कों से पीने के पानी की सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है। कोलकाता के लोगों को दूर भविष्य में पानी की दिक्कतों से न जूझना पड़े, इसके लिए खास पहल की गई है। वॉटर प्रोजेक्ट गार्डन रीच कचरा डिपो पर बनेगा। कोलकाता नगर निगम के मासिक सत्र में सवाल-जवाब के दौरान वार्ड नंबर 48 के पार्षद विस्वरूप डे ने कोलकाता में पीने के पानी से जुड़े सवाल पूछे।

जवाब में फिरहाद ने कहा कि वॉटर प्रोजेक्ट गार्डन रीच कचरा डिपो पर बनेगा। वॉटर प्रोजेक्ट के लिए मेयर ने खुद जमीन चुनी है। इस वॉटर प्रोजेक्ट से 40 मिलियन गैलन पानी बनेगा। कोलकाता नगर निगम ने इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार से इजाजत मांगी है। नवान्न से हरी झंडी मिलने पर काम शुरू हो जाएगा। और इस वॉटर प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद, कोलकाता में अगले 25 सालों में भी पानी की कोई समस्या नहीं होगी।

गौरतलब है कि कोलकाता में घरों की संख्या धीरे-धीरे कम हो रही है। गलियों में भी मल्टी-स्टोरी बिल्डिंग बन रही हैं। नतीजतन, शहर के लोगों की पानी की मांग दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है। इस संबंध में, पार्षद विस्वरूप डे ने हाई-पावर पंप की मदद से ग्राउंडवाटर निकालने की व्यवस्था पर सवाल उठाए। पार्षद जानना चाहते थे कि क्या नगर निगम इस मुद्दे पर ध्यान दे रही है। मेयर फिरहाद हकीम ने कहा कि कोलकाता नगर पालिका इस मुद्दे पर कड़ी नज़र रखे हुए है। मेयर द्वारा दिए गए वॉटर प्रोजेक्ट के निर्माण की अच्छी खबर से कोलकाता के लोग खुश हैं। देखना यह है कि वॉटर प्रोजेक्ट कब लागू होता है।

गौरतलब है कि कोलकाता में गार्डन रीच वॉटर प्रोजेक्ट है। उनके अधिकार क्षेत्र में कालीघाट, रानीकुठी, बंशद्रोनी, गरफा, चेतला, गोल्फ ग्रीन, बेहाला, दासपाड़ा, गांधी मैदान, सेनपल्ली, प्रफुल्ल पार्क, पर्णश्री, मटियाबुरूज और शकुंतला पार्क बूस्टर पंपिंग स्टेशन आते हैं। इन पंपिंग स्टेशनों से दक्षिण कोलकाता के एक बड़े इलाके में पीने का पानी सप्लाई होता है। कुछ ही महीनों बाद राज्य में विधानसभा चुनाव हैं। इसमें कोई शक नहीं कि उससे पहले फिरहाद ने पानी के प्रोजेक्ट की जो खुशखबरी दी है, वह काफी अहम है।

भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दार्जिलिंग चाय का एक्सपोर्ट बढ़ेगा

चैंबर ऑफ कॉमर्स ने जताई उम्मीद

निज संवाददाता : भारत-यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से दार्जिलिंग चाय का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, चैंबर ऑफ इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से उत्तर बंगाल के चाय बेल्ट में खुशी की लहर दौड़ गई है। टी चैंबर ऑफ कॉमर्स का दावा है कि इस एग्रीमेंट से चाय इंडस्ट्री के लिए नए अंतरराष्ट्रीय बाजार खुलेंगे। इससे भारतीय चाय की क्वालिटी और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से इसकी स्वीकार्यता सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इसलिए, इससे यूरोपियन कंज्यूमर्स के बीच भारतीय चाय की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज के वाइस चेयरमैन और दार्जिलिंग हिल्स के चाय इंडस्ट्रियलिस्ट सतीश मित्रुका ने कहा-भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच हुए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से इंडियन चाय इंडस्ट्री को बहुत फायदा होगा। खासकर दार्जिलिंग चाय को। उन्होंने कहा कि अभी हर साल 5.25 मिलियन केजी दार्जिलिंग चाय का प्रोडक्शन होता है। जिसमें से 4 मिलियन केजी एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अभी तक भारत से 2 मिलियन केजी चाय जर्मनी जाती थी। वहां से यह इटली, फ्रांस समेत कई देशों में पहुंचती थी। इस एग्रीमेंट की वजह से अब फ्रांस और इटली समेत कई यूरोपियन देशों में सीधे दार्जिलिंग चाय भेजना मुमकिन हो जाएगा। कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन स्मॉल टी ग्रोअर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष विजयगोपाल चक्रवर्ती ने कहा-भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से चाय का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। ज़ाहिर है, इससे पूरी चाय इंडस्ट्री को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि दार्जिलिंग और नॉर्थ-ईस्ट में 1 मिलियन यानी 10 लाख वर्कर सीधे तौर पर चाय इंडस्ट्री पर और 6 मिलियन यानी 60 लाख लोग इनडायरेक्टली निर्भर हैं। हालांकि, यहां की चाय इंडस्ट्री क्लाइमेट चेंज, कीमत की अनिश्चितता और कम क्वालिटी वाली चाय के इंपोर्ट की वजह से चुनौतियों का सामना कर रही है। क्लाइमेट चेंज की वजह से पिछले साढ़े पांच दशकों में दार्जिलिंग चाय का प्रोडक्शन खतरनाक रूप से कम हुआ है।

1970 में प्रोडक्शन 14 मिलियन केजी था, जो घटकर 5.25 मिलियन केजी रह गया है। नए एग्रीमेंट की वजह से यूरोपियन मार्केट में खास एक्सेस मिलने से दार्जिलिंग चाय का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। चाय ट्रेड एसोसिएशन के मुताबिक, भारत-यूई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारतीय चाय इंडस्ट्री में नई जान डाल सकता है। इस एग्रीमेंट से यूरोपियन मार्केट तक एक्सेस आसान होगा, खासकर असम और दार्जिलिंग चाय के लिए, और टैरिफ कम होंगे। यह ऐतिहासिक एग्रीमेंट चाय एक्सपोर्ट बढ़ाने, प्रोड्यूसर्स की इनकम बढ़ाने और ग्लोबल कॉम्पिटिशन में इंडियन टी इंडस्ट्री को मज़बूत करने में मदद करेगा। इस एग्रीमेंट से 97 से 99 फीसद उत्पादों पर टैरिफ कम या खत्म हो सकते हैं। इससे यूरोपियन मार्केट में भारतीय चाय की कीमत कम होगी और यह प्रतिस्पर्धी बनेगी। चाय एक्सपोर्ट बढ़ेगा और चाय इंडस्ट्री से जुड़े छोटे ट्रेडर्स के लिए नौकरियां पैदा होंगी। यह एग्रीमेंट भारतीय चाय की क्वालिटी और यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के कम्प्लायंस को पक्का करने में भी मदद करेगा। इससे यूरोपियन कंज्यूमर्स के बीच भारतीय चाय की स्वीकार्यता बढ़ेगी।

एसआईआर सुनवाई केंद्र में शादी के जोड़े में पहुंचा युवक

निज संवाददाता : एसआईआर हियरिंग केंद्र (सुनवाई केंद्र) के बाहर लंबी लाइन लगी है। हर कोई हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए खड़ा है। अचानक, सबका ध्यान शादी के जोड़ा पहने एक युवक पर जाता है। वह अकेला नहीं है, बल्कि कुछ और लोगों के साथ है। वे दूल्हे के मेहमान हैं। हियरिंग में आए लोकल लोग हियरिंग केंद्र में शादी का जोड़ा पहने युवक के अचानक आने से हैरान रह गए। उन्होंने पूछताछ की। युवक भी हियरिंग नोटिस लेकर आया था। उसकी शादी शुक्रवार को थी। और उसी दिन समन जारी हुआ था। इसलिए शादी करने जाने से पहले, युवक हियरिंग सेंटर गया! स्थानीय सूत्रों के मुताबिक, मुर्शिदाबाद के रघुनाथगंज-2 ब्लॉक के सन्मतिनगर ग्राम पंचायत के रहने वाले नयन शेख की शादी की तारीख 30 जनवरी, शुक्रवार तय हुई थी। जब शादी की तैयारियां जोरों पर थीं, तो एक दिन अचानक एसआईआर हियरिंग नोटिस उसके घर पहुंच गया। इसमें कहा गया कि उसे 30 जनवरी को ज़रूरी कागज़ात के साथ सुनवाई केंद्र में पेश होना होगा। पहले तो नयन इस मामले को लेकर झिझका। लेकिन, सोचने के बाद उसने शादी करने से पहले सुनवाई केंद्र जाने का फ़ैसला किया। वह शुक्रवार को अपनी दुल्हन के साथ सुनवाई केंद्र पहुंचा। सुनवाई के दौरान राज्य के बिजली राज्य मंत्री अख़रुज़्ज़मान भी मौजूद थे। वह भी नयन को शादी के जोड़े में सुनवाई केंद्र में आया देखकर हैरान रह गए। सब कुछ जानने के बाद उन्होंने नयन की सुनवाई जल्दी पूरी करने के लिए कार्रवाई की। अख़रुज़्ज़मान ने कहा-ऐसा अक्सर नहीं देखा जाता कि नौजवान अपने अधिकारों की रक्षा के लिए सतर्क रहते हुए शादी के जोड़े में तैयार होकर सुनवाई में आए। मामले की जानकारी होने के बाद हमने तुरंत कदम उठाए ताकि वह अपना काम पूरा कर सके और समय पर शादी कर सके। मंत्री की मौजूदगी में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ नयन की सुनवाई की प्रक्रिया जल्दी पूरी की गई। एसआईआर का सारा काम पूरा करने के बाद वह शादी के लिए निकल गया।

केंद्र की आर्थिक सर्वे रिपोर्ट में हुआ खुलासा

ग्रोथ रेट में बिहार, झारखंड, ओडिशा से पश्चिम बंगाल पीछे

निज संवाददाता : बीते गुरुवार को संसद में जारी आर्थिक सर्वे रिपोर्ट (2025-26) में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में पश्चिम बंगाल का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (एनएसडीपी) 9.86 फीसद बढ़कर 16.32 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि केंद्रीय वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट में राज्य के आर्थिक विकास को माना गया है, लेकिन कहा गया है कि पश्चिम बंगाल अपने पड़ोसी राज्यों से पीछे है। पिछले वित्तीय वर्ष (2023-24) में पश्चिम बंगाल में एनएसडीपी ग्रोथ रेट 8.94 फीसद थी।

हालांकि यह उससे बेहतर है, लेकिन पश्चिम बंगाल अभी भी तमिलनाडु (15.76 फीसद) और उत्तर प्रदेश (12.64 फीसद) जैसे बड़े राज्यों से पीछे है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा गुरुवार को संसद में पेश की गई इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि 2023-24 में राज्य का एनएसडीपी 14.85 लाख करोड़ रुपये था। निर्मला की रिपोर्ट कहती है कि 2024-25 में बिहार की एनएसडीपी ग्रोथ 13.07 फीसद, ओडिशा की 13.04 फीसद और झारखंड की 10.88 फीसद है। यानी, इस मामले में पश्चिम बंगाल पूर्वी भारत के अपने तीन पड़ोसी राज्यों से पीछे है। हालांकि, राज्य उत्तर भारत के कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से बेहतर स्थिति में है। एनएसडीपी ग्रोथ पंजाब (9.12 फीसद) और दिल्ली (9.28 फीसद) से ज़्यादा है। दूसरे राज्यों में, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2024-25 में क्रमशः 12.79 फीसद और 12.28 फीसद की एनएसडीपी ग्रोथ देखी गई है। वैसे, 2021-22 में महामारी के बाद के दौर में पश्चिम बंगाल की एनएसडीपी ग्रोथ रेट 17.55 फीसद थी।

संगीत के भव्य आयोजन में कजाकिस्तान और भारतीय कलाकारों ने समां बांधा

- अलग-अलग भाषा के लोगों को संगीत ने एक किया

निज संवाददाता : महानगर कोलकाता में हाल ही में एक बहुत खूबसूरत संगीत कार्यक्रम 'लक्ष्मीनारायण ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल' हुआ। यह कार्यक्रम उत्तर कोलकाता के टाला प्रत्याय में हुआ, जहां पार्क में ही मंच सजाया गया था। इसलिए इसे म्यूजिक इन ए पार्क कहा गया। देवी सरस्वती की मूर्ति के सामने पूरा कार्यक्रम चला और आसपास चांदनी रात में एक छोटा-सा मेला भी लगा था।इस कार्यक्रम में बड़े-बड़े कलाकारों ने शिरकत की। प्रसिद्ध वायलिन वादक डॉ. एल. सुब्रमण्यम ने अपनी पुरानी रचना शांतिप्रिया बजाई, जो उन्होंने 1980 के दशक में बनाई थी। इस बार कजाकिस्तान का गक्कू बैले ग्रुप ने इसके साथ डांस परफॉर्मेंस भी दी। साथ ही उनकी नवग्रह सिम्फनी भी सुनाई गई, जिसमें कजाकिस्तान का कोरस गाया। भारतीय गायिका कविता कृष्णमूर्ति ने भी संगीत से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया। तबला पर तन्मय बोस, मृदंगम पर वी.वी. रामनमूर्ति और कंजीरा पर स्वामीनाथन सेल्वगणेश ने साथ दिया।खास बात यह थी कि कजाकिस्तान से अस्ताना फिलहार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और उनका चैंबर कोर पहली बार इतने बड़े स्तर पर कोलकाता आया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और कजाकिस्तान के संगीत-नृत्य का ऐसा सुंदर मेल पहली बार देखने को मिला। भाषा अलग थी, देश अलग थे, लेकिन संगीत ने सबको एक कर दिया। दर्शकों ने खूब तालियां बजाईं और बहुत आनंद उठाया।कोलकाता के मेयर फरहाद हाकिम और विधाननगर की मेयर कृष्णा चक्रवर्ती भी वहां मौजूद थे। कविता कृष्णमूर्ति ने कहा कि कोलकाता संगीत और संस्कृति का शहर है। यहां परफॉर्म करना हमेशा अच्छा लगता है और सरस्वती मां के सामने गाना तो और भी खास था। डॉ. एल. सुब्रमण्यम ने बताया कि कोलकाता के लोग क्लासिकल और ऑर्केस्ट्रा संगीत दोनों को बहुत समझते हैं। सरस्वती मां की मूर्ति पीछे होने से लगा जैसे वो आशीर्वाद दे रही हैं। इस कार्यक्रम के आयोजक ध्रुवज्योति बसु ने कहा कि यह फेस्टिवल का चौथा साल है। हर साल सरस्वती पूजा से पहले ऐसा कार्यक्रम करते हैं ताकि बंगाली संस्कृति को नया रूप मिले और कोलकाता को कुछ नया और अलग देने का मौका मिले। पूरा माहौल ऐसा था जैसे संस्कृति का बड़ा मेला लग गया हो। संगीत ने बिना किसी भाषा के सबके दिल को छू लिया और यह शाम सबके लिए यादगार बन गई।

900 दिनों से ज़्यादा समय तक खुला रहा लड़की का मुंह!

दुर्लभ आपरेशन के बाद सामान्य हुई हालत

निज संवाददाता : एक सरकारी डेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने एक नाबालिग लड़की का मुंह बंद करने में मदद की है, जिसका मुंह एक रेयर ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी तंत्रिका संबंधी विकार) की वजह से 900 दिनों से ज़्यादा समय तक खुला रहा था। यह जानकारी चिकित्सा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने दी।

दरअसल, करीब 10 साल की बच्ची एक ऐसे हालात से जूझ रही थी जिससे उसके जबड़े और चेहरे की मसल्स को कंट्रोल करने वाली नर्व्स डैमेज हो गई थीं, जिससे वह लगभग 912 दिनों तक अपना मुंह बंद नहीं कर पाई थी। बंगाल के अंदर और बाहर कई अस्पतालों में इलाज के बावजूद, उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। तब, बच्ची आखिरकार आर अहमद डेंटल कॉलेज और हॉस्पिटल में इलाज के बाद अपना मुंह बंद कर पा रही है। अस्पताल के एक वरिष्ठ डॉक्टर ने बताया-वह एक्यूट डिसेमिनेटेड एन्सेफेलोमाइलाइटिस (तीव्र प्रसारित एन्सेफेलोमाइलाइटिस) यानी एडीईओम से जूझ रही थी, जो एक रेयर ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर (दुर्लभ स्वप्रतिरक्षी तंत्रिका संबंधी विकार) है जिसमें इम्यून सिस्टम ब्रेन (प्रतिरक्षा प्रणाली मस्तिष्क) और स्पाइनल कॉर्ड (मेरुदंड) पर अटैक करता है। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक मुंह बंद न कर पाने की वजह से कई दिक्कतें हुई हैं, जिसमें मुंह का सूखना, जबड़े का संतुलन बिगड़ना और दांतों का ऊपर की ओर असामान्य रूप से हिलना शामिल है, जिसे सुप्रा-इरप्शन (सुप्रा-विस्फोट) कहते हैं। उन्होंने आगे कहा-क्योंकि उसका मुंह इतने लंबे समय तक खुला रहा, दांत अपनी सामान्य जगह से काफी हट गए थे, जिससे इन्फेक्शन और परमानेंट डैमेज का खतरा बढ़ गया था। इलाज की प्लानिंग के लिए अस्पताल में एक स्पेशल मेडिकल बोर्ड बनाया गया था। विस्तार से जांच के बाद, डॉक्टरों ने यह नतीजा निकाला कि मुंह बंद करना मेडिकली जरूरी हो गया था। इलाज में शामिल एक डॉक्टर ने कहा-इस मामले में, जबड़े को बंद करने और आगे की दिक्कतों को रोकने के लिए पीछे के दांतों को निकालना ही एकमात्र प्रैक्टिकल ऑप्शन था। हाल ही में किए गए प्रोसीजर (प्रक्रिया) के बाद, लड़की अब अपना मुंह बंद कर सकती है।

डॉक्टर ने आगे कहा-इस इंटरवेंशन (हस्तक्षेप) से भविष्य में दांतों के खराब होने और मुंह के इन्फेक्शन का खतरा काफी कम हो जाएगा। एडीईएम का इलाज साथ-साथ चल रहा है। अस्पताल के अधिकारियों ने इस मामले को दुर्लभ बताया और कहा कि यह मुश्किल न्यूरोलॉजिकल और डेंटल कंडीशन को मैनेज करने में कोऑर्डिनेटेड, स्पेशलाइज्ड केयर (समन्वित, विशेषीकृत देखभाल) के महत्व को दिखाता है।

हल करो हीरो बनो का उत्तर

1)लमन, 2)12,000 करोड़, 3)1995, 4)रसिया, 5)क्लोरीन,

संपादकीय

सही कदम : जातिगत भेदभाव पर यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

उच्च शिक्षण संस्थान, जिन्हें बराबरी का गढ़ और सामाजिक मेलजोल को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए, वे अक्सर कमज़ोर समूह के खिलाफ खुले या हल्के भेदभाव की वजह से होने वाले छात्र आत्महत्या को रोकने में नाकाम लगते हैं। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले बनाई गई नेशनल टास्क फोर्स (एनटीएफ) ने पाया था, पढ़ाई का तनाव भी एक वजह हो सकता है। कई मामलों में, दोनों वजहें जुड़ी हुई हैं। अलग-अलग सेल के ज़रिए संस्थानों को सबको साथ लेकर चलने वाला, ज़िम्मेदार और जवाबदेह बनाने के लिए गाइडलाइंस की कमी नहीं है ताकि बराबरी और यौन न्याय पक्का हो सके। हालांकि, एनटीएफ ने पाया कि उनका लागू होना अक्सर गायब या अधूरा था, जो सामाजिक शक्ति के कामों से जुड़ा हुआ था। 15 इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ़ टेक्नोलॉजी (आईआईटी), जो खुद को बेहतरीन मानते हैं, में जुलाई 2023 से 40 छात्रों ने आत्महत्या की, जब केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने उच्च शिक्षण संस्थानों को अपने छात्रों की मानसिक और भावनात्मक भलाई पक्का करने के लिए गाइडलाइंस जारी की थीं। 2021 और 2025 के बीच, आईआईटी में 67 छात्रों ने आत्महत्या की। एनटीएफ ने बताया कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (एनसीबी) के डेटा के मुताबिक, 2022 में उच्च शिक्षण संस्थानों में 13,000 से ज़्यादा छात्रों ने आत्महत्या की। अब, सुप्रीम कोर्ट को नए यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन्स में इक्विटी को बढ़ावा देना) रेगुलेशंस, 2026 पर रोक लगानी पड़ी है, जो जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए बनाए गए थे। नॉन-रिज़र्व्ड या जनरल कैटेगरी के छात्र विरोध कर रहे हैं कि उन्हें इन रेगुलेशंस से मिलने वाली संस्थागत संरक्षण से बाहर रखा जा रहा है। यानी, यूजीसी के रेगुलेशंस एक्सक्लूज़नरी हैं। उनका इस्तेमाल नॉन-रिज़र्व्ड स्टूडेंट्स के खिलाफ किया जा सकता है। यह बदलाव केंद्र सरकार को खुश नहीं कर सकता। जनरल कैटेगरी के युवाओं के विरोध से उसकी संबंधित अधिकार और समानता को बढ़ावा देने वाली इमेज खराब होती है। सुप्रीम कोर्ट इन रेगुलेशंस को चुनौती देने वाली पिटीशन्स (याचिकाओं) पर सुनवाई कर रहा था और उसने पाया कि रेगुलेशंस की भाषा साफ़ नहीं है और इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। इनकी जांच एक एक्सपर्ट कमेटी से करवानी होगी। कोर्ट ने इस बात की भी तरफ इशारा किया कि एक रेगुलेशन सिर्फ़ जाति के आधार पर भेदभाव पर फोकस करता है, यानी जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या दूसरे पिछड़े वर्ग के छात्रों के खिलाफ होता है, और दूसरा सभी तरह के भेदभाव के खिलाफ है। यह आखिरी प्रोविज़न यूजीसी के 2012 के रेगुलेशन में पहले से ही मौजूद था। यह सही और न्यायसंगत है कि सुप्रीम कोर्ट चाहे कि भ्रम और विसंगति को दूर किया जाए, वरना कोई भी रेगुलेशन असरदार नहीं हो सकता। लेकिन यूजीसी, जो बराबरी हासिल करने के अपने घोषित मकसद के साथ है, भ्रामक और शायद बांटने वाले रेगुलेशन क्यों बनाए? जब भी संस्थान और राज्य सामाजिक भेदभाव को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो एक बुनियादी कमी काम करती हुई लगती है। असल में, 2010 तक आज के समय में भेदभाव का कोई आधिकारिक ज़िक्र नहीं था। आज़ादी के बाद, समाज को एक साथ लाने की कोशिश ने असमानता के प्रति अंधापन पैदा किया, जिसे विविधता और किस्मत का बनाया पिछड़ापन कहा गया। यह एक ऐसी आदत लगती है जिससे छुटकारा पाना मुश्किल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने समाज को बांटने वाले, कन्फ्यूज़ करने वाले नियमों पर रोक लगाकर सही किया, लेकिन असली मुद्दा सामाजिक भेदभाव की वजह से बहुत सारे छात्रों का आत्महत्या करना दुख की बात है। यह बर्दाश्त के बाहर है और इसे ठीक किया जाना चाहिए।

आर्थिक सर्वेक्षण से बजट तक : भविष्य के भारत की तलाश

ललित गर्ग

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा संसद के पटल पर प्रस्तुत किया जाने वाला बजट केवल आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा नहीं होता, बल्कि वह देश की आर्थिक दिशा, सामाजिक प्राथमिकताओं और भविष्य की संभावनाओं का दर्पण होता है। आज जब भारत एक ओर तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था के रूप में विश्व मंच पर अपनी पहचान मजबूत कर रहा है और दूसरी ओर वैश्विक अनिश्चितताओं, भू-राजनीतिक तनावों, जलवायु संकट और तकनीकी परिवर्तन की चुनौतियों से जूझ रहा है, तब यह बजट और भी अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। व्यक्तिगत नागरिक से लेकर व्यापारी, उद्योगपति, किसान, श्रमिक, युवा और मध्यम वर्ग-सभी की निगाहें इस बजट पर टिकी हैं, क्योंकि इससे न केवल वर्तमान वर्ष की आर्थिक तस्वीर, बल्कि ''भविष्य के भारत'' की झलक भी मिलती है। बजट से पूर्व प्रस्तुत आर्थिक सर्वेक्षण ने सरकार की सोच और नीति-दृष्टि के कई संकेत दिए हैं। इसमें विकास को केवल आंकड़ों की वृद्धि तक सीमित न रखकर अवसरों के विस्तार, समावेशी विकास और दीर्घकालिक स्थिरता पर जोर दिया गया है। यह स्वीकार किया गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था के सामने चुनौतियां अवश्य हैं, किंतु उनसे अधिक संभावनाएं हैं। यही दृष्टिकोण इस बजट का मूल स्वर होना चाहिए-चुनौतियों को अवसरों में बदलने का साहसिक प्रयास। सबसे पहली और महत्वपूर्ण अपेक्षा निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने को लेकर है। किसी भी अर्थव्यवस्था की वास्तविक मजबूती तभी आती है जब उसके सबसे निचले पायदान पर खड़ा व्यक्ति भी सम्मानजनक जीवन जी सके और उपभोग में भागीदार बने। यदि निम्न आय वर्ग की आय बढ़ती है, उसे सस्ती और सुलभ सुविधाएं मिलती हैं, तो उसका सीधा प्रभाव मांग पर पड़ता है और मांग बढ़ने से उत्पादन, निवेश और रोजगार-तीनों को गति मिलती है। इसलिए इस बजट में प्रत्यक्ष नकद अंतरण, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और शिक्षा पर खर्च के साथ-साथ रोजगार सृजन के ठोस उपाय अपेक्षित हैं। मनरेगा जैसे कार्यक्रमों का सुदृढ़ीकरण, शहरी गरीबों के लिए भी समान प्रकृति की योजनाएं और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकते हैं। शहरी विकास इस बजट का एक और प्रमुख केंद्र होना चाहिए। भारत तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है और शहरों पर जनसंख्या, आवास, परिवहन, जल, स्वच्छता और पर्यावरण का दबाव लगातार बढ़ रहा है। केवल बड़े महानगरों पर

निर्भरता अब व्यावहारिक नहीं रही। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा द्वारा सुझाया गया शहरी विकेंद्रीकरण का विचार आज के संदर्भ में अत्यंत प्रासंगिक है। छोटे और मध्यम शहरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बनाना, उद्योगों और सेवाओं को वहां प्रोत्साहित करना, न केवल महानगरों पर बोझ कम करेगा बल्कि क्षेत्रीय असंतुलन को भी घटाएगा। बजट में यदि टियर-2 और टियर-3 शहरों के लिए विशेष शहरी अवसंरचना पैकेज, परिवहन नेटवर्क, डिजिटल कनेक्टिविटी और कौशल विकास योजनाएं लाई जाती हैं, तो यह दूरगामी परिवर्तन का आधार बन सकता है। वैश्विक स्तर पर टैरिफ, व्यापार अवरोध और संरक्षणवाद की प्रवृत्तियां भारत के लिए चुनौती भी हैं और अवसर भी। अजय बंगा का यह कथन कि टैरिफ पर अधिक चिंता करने के बजाय व्यापारिक अवसरों पर ध्यान दिया जाना चाहिए, भारत की वर्तमान स्थिति के लिए उपयुक्त दृष्टि प्रदान करता है। भारत के पास विशाल घरेलू बाजार, युवा जनसंख्या, डिजिटल क्षमताएं और उद्यमशीलता की प्रबल ऊर्जा है। यदि यह बजट निर्यात-उन्मुख उद्योगों, स्टार्ट-अप्स, मैन्युफैक्चरिंग और वैल्यू-एडेड सेक्टर को प्रोत्साहन देता है, तो भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में और मजबूत स्थान बना सकता है। 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' को केवल नारों से आगे ले जाकर व्यावहारिक नीति समर्थन की आवश्यकता है-सरल कर संरचना, आसान ऋण, अनुसंधान एवं नवाचार में निवेश और व्यापार करने में सुगमता के माध्यम से।

इस संदर्भ में मध्यम वर्ग की भूमिका को नजरअंदाज करना आर्थिक दृष्टि से आत्मघाती होगा। मध्यम वर्ग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है-वह सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है और सबसे बड़ा करदाता भी। विडंबना यह है कि बजट चर्चाओं में अक्सर यही वर्ग अपेक्षाकृत उपेक्षित रह जाता है। बढ़ती महंगाई, शिक्षा और स्वास्थ्य का खर्च, आवास ऋण और करों का बोझ मध्यम वर्ग की बचत और उपभोग दोनों को प्रभावित करता है। यदि इस बजट में आयकर स्लैब में तर्कसंगत सुधार, शिक्षा-स्वास्थ्य पर कर राहत और आवास को प्रोत्साहन जैसे कदम उठाए जाते हैं, तो इससे न केवल मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी बल्कि मांग-आधारित विकास को भी बल मिलेगा।

उद्योगों और व्यापार जगत के लिए बजट से अपेक्षा है कि वह स्थिर और पूर्वानुमेय नीति वातावरण प्रदान करे। निवेशक अनिश्चितता से डरते हैं। कर नीति में बार-बार बदलाव, अनुपालन की जटिलता और नियामक अस्पष्टता निवेश को बाधित करती है। इस बजट में यदि दीर्घकालिक कर-नीति का स्पष्ट संकेत, एमएसएमई सेक्टर के लिए सस्ता ऋण, तकनीकी उन्नयन के लिए प्रोत्साहन और हरित उद्योगों के लिए विशेष पैकेज दिए जाते हैं, तो यह उद्योगों के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। विशेष रूप से एमएसएमई क्षेत्र, जो रोजगार का सबसे बड़ा स्रोत है, उसे आर्थिक पुनरुत्थान का केंद्र बनाया जाना चाहिए। भविष्य के भारत की कल्पना केवल आर्थिक वृद्धि तक सीमित नहीं हो सकती। इसमें पर्यावरणीय स्थिरता, सामाजिक न्याय और मानवीय विकास समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में हरित ऊर्जा, स्वच्छ परिवहन और टिकाऊ कृषि को बजट में प्राथमिकता मिलनी चाहिए। यह न केवल पर्यावरण की रक्षा करेगा, बल्कि नए उद्योगों और रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा। शिक्षा और कौशल विकास में निवेश भविष्य की कार्यशक्ति को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगा, जबकि स्वास्थ्य पर खर्च एक स्वस्थ और उत्पादक समाज की नींव रखेगा। अंततः यह बजट एक संतुलन की परीक्षा है-राजकोषीय अनुशासन और विकासात्मक खर्च के बीच, अल्पकालिक राहत और दीर्घकालिक सुधारों के बीच, तथा विभिन्न वर्गों की अपेक्षाओं के बीच। यदि यह बजट निम्न वर्ग की क्रय-शक्ति बढ़ाने, मध्यम वर्ग को राहत देने, शहरी विकेंद्रीकरण को गति देने और वैश्विक चुनौतियों को अवसरों में बदलने की स्पष्ट दिशा देता है, तो यह केवल एक वित्तीय दस्तावेज नहीं, बल्कि ''विकसित भारत'' की ओर बढ़ते कदम का घोषणापत्र बन सकता है। देश को आज ऐसे ही बजट की आवश्यकता है-जो आशा जगाए, विश्वास पैदा करे और भविष्य के प्रति एक सकारात्मक, साहसिक दृष्टि प्रस्तुत करे।

जानें अपना राशिफल

मेष

पुरे दिन की मेहनत शाम तक अच्छा फायदा दे सकती है, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, किसी नये व्यक्ति से काम आगे बढ़ सकता है, मन में उत्साह रहेगा।

वृषभ

उर्जावान समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई रुका हुआ मांगलिक कार्य पुरा हो सकता है प्रयास करे, जीवनसाथी पूरा साथ दे सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा।

मिथुन

चुनौती भरा समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई अधूरा काम पूरा हो सकता है, मन स्थिर रखे।

कर्क

सकारात्मक समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई चमत्कारी काम बन सकता है, पूरी नैतिकता से काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

सिंह

आनन्द वाला समय हो सकता है इसलिए जो भी काम कर रहे हैं फायदा अवश्य होगा, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

कन्या

उत्साह भरा समय हो सकता है, किसी अन्य व्यक्ति से काम करने पर विचार हो सकता है जो फायदेमंद होगा, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

तुला

निर्णायक भूमिका निभाने वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ मांगलिक कार्य पूरा हो सकता है प्रयास करे, मित्र पूरा साथ दे सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा।

वृश्चिक

घुटन वाला समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई परिवार का सदस्य आपका समय खराब कर सकता है, मन वश में रखे।

धनु

प्रतिभाशाली समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, कोई बड़ा काम करने का अवसर मिल सकता है, मन शान्त रखे।

मकर

प्रशंसा वाला समय हो सकता है, कोई बहुत दिनों से रुका हुआ काम आगे बढ़ सकता है प्रयास करे, किसी पर भरोसा करके काम करने की आवश्यकता है, मन प्रसन्न रहेगा।

कुंभ

मेहनत भरा समय हो सकता है इसलिए ज्यादा से ज्यादा काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, पूरी नैतिकता से काम करने की आवश्यकता है, मन स्थिर रखे।

मीन

साधारण समय हो सकता है इसलिए सिर्फ काम करने पर ध्यान रखने की आवश्यकता है, किसी के बहकावे में आने से बचने की आवश्यकता है, मन शान्त रखे।

गुरु की सिख

एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरु जी से पूछा- 'गुरु जी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ अन्य कहते हैं कि जीवन एक खेल है और कुछ जीवन को एक उत्सव की संज्ञा देते हैं। इनमें कौन सही है?'

गुरु जी ने तत्काल बड़े ही धैर्यपूर्वक उत्तर दिया- पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिला उनके लिए जीवन एक संघर्ष है; जिन्हें गुरु मिल गया उनका जीवन एक खेल है और जो लोग गुरु द्वारा बताये गए मार्ग पर चलने लगते हैं, मात्र वे ही जीवन को एक उत्सव का नाम देने का साहस जुटा पाते हैं। यह उत्तर सुनने के बाद भी शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट न था। गुरु जी को इसका आभास हो गया। वे कहने लगे- 'लो, तुम्हें इसी सन्दर्भ में एक कहानी सुनाता हूँ। ध्यान से सुनोगे तो स्वयं ही अपने प्रश्न का उत्तर पा सकोगे।'

एक बार की बात है कि किसी गुरुकुल में तीन शिष्यों नें अपना अध्ययन सम्पूर्ण करने पर अपने गुरु जी से यह बताने के लिए विनती की कि उन्हें गुरुदाक्षिणा में, उनसे क्या चाहिए। गुरु जी पहले तो मंद-मंद मुस्कराये और फिर बड़े स्नेहपूर्वक कहने लगे-'मुझे तुमसे गुरुदक्षिणा में एक थैला भर के सूखी पत्तियां चाहिए, ला सकोगे?' वे तीनों मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए क्योंकि उन्हें लगा कि वे बड़ी आसानी से अपने गुरु जी की इच्छा पूरी कर सकेंगे। सूखी पत्तियाँ तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती हैं। वे उत्साहपूर्वक एक ही स्वर में बोले-'जी गुरु जी, जैसी आपकी आज्ञा।' अब वे तीनों शिष्य चलते-चलते एक समीपस्थ जंगल में पहुँच चुके थे। लेकिन यह देखकर कि वहाँ पर तो सूखी पत्तियाँ केवल एक मुट्ठी भर ही थीं, उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वे सोच में पड़ गये कि आखिर जंगल से कौन सूखी पत्तियां उठा कर ले गया होगा? इतने में ही उन्हें दूर से आता हुआ कोई किसान दिखाई दिया। वे उसके पास पहुँच कर, उससे विनम्रतापूर्वक याचना करने लगे कि वह उन्हें केवल एक थैला भर सूखी पत्तियां दे दे। अब उस किसान ने उनसे क्षमायाचना करते हुए, उन्हें यह बताया कि वह उनकी मदद नहीं कर सकता क्योंकि उसने सूखी पत्तियों का ईंधन के रूप में पहले ही उपयोग कर लिया था। अब, वे तीनों, पास में ही बसे एक गाँव की ओर इस आशा से बढ़ने लगे थे कि हो सकता है वहाँ उस गाँव में उनकी कोई सहायता कर सके। वहाँ पहुँच कर उन्होंने जब एक व्यापारी को देखा तो बड़ी उम्मीद से उससे एक थैला भर सूखी पत्तियां देने के लिए प्रार्थना करने लगे लेकिन उन्हें फिर से एकबार निराशा ही हाथ आई क्योंकि उस व्यापारी ने तो, पहले ही, कुछ पैसे कमाने के लिए सूखी पत्तियों के दोने बनाकर बेच दिए थे लेकिन उस व्यापारी ने उदारता दिखाते हुए उन्हें एक बूढी माँ का पता बताया जो सूखी पत्तियां एकत्रित किया करती थी। पर भाग्य ने यहाँ पर भी उनका साथ नहीं दिया क्योंकि वह बूढी माँ तो उन पत्तियों को अलग-अलग करके कई प्रकार की ओषधियाँ बनाया करती थी। अब निराश होकर वे तीनों खाली हाथ ही गुरुकुल लौट गये। गुरु जी ने उन्हें देखते ही स्नेहपूर्वक पूछा- 'पुत्रो, ले आये गुरुदक्षिणा?' तीनों ने सर झुका लिया। गुरू जी द्वारा दोबारा पूछे जाने पर उनमें से एक शिष्य कहने लगा- 'गुरुदेव, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाये। हमने सोचा था कि सूखी पत्तियां तो जंगल में सर्वत्र बिखरी ही रहती होंगी लेकिन बड़े ही आश्चर्य की बात है कि लोग उनका भी कितनी तरह से उपयोग करते हैं। 'गुरु जी फिर पहले ही की तरह मुस्कराते हुए प्रेमपूर्वक बोले-'निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ और यही ज्ञान कि सूखी पत्तियां भी व्यर्थ नहीं हुआ करतीं बल्कि उनके भी अनेक उपयोग हुआ करते हैं; मुझे गुरुदक्षिणा के रूप में दे दो। 'तीनों शिष्य गुरु जी को प्रणाम करके खुशी-खुशी अपने-अपने घर की ओर चले गये। वह शिष्य जो गुरु जी की कहानी एकाग्रचित्त हो कर सुन रहा था, अचानक बड़े उत्साह से बोला-'गुरु जी, अब मुझे अच्छी तरह से ज्ञात हो गया है कि आप क्या कहना चाहते हैं। आप का संकेत, वस्तुतः इसी ओर है न कि जब सर्वत्र सुलभ सूखी पत्तियां भी निरर्थक या बेकार नहीं होती हैं तो फिर हम कैसे, किसी भी वस्तु या व्यक्ति को छोटा और महत्त्वहीन मान कर उसका तिरस्कार कर सकते हैं? चींटी से लेकर हाथी तक और सुई से लेकर तलवार तक-सभी का अपना-अपना महत्त्व होता है। गुरु जी भी तुरंत ही बोले-'हाँ, पुत्र,मेरे कहने का भी यही तात्पर्य है कि हम जब भी किसी से मिलें तो उसे यथायोग्य मान देने का भरसक प्रयास करें ताकि आपस में स्नेह, सद्भावना, सहानुभूति एवं सहिष्णुता का विस्तार होता रहे और हमारा जीवन संघर्ष के बजाय उत्सव बन सके। दूसरे, यदि जीवन को एक खेल ही माना जाए तो बेहतर यही होगा कि हम निर्विक्षेप, स्वस्थ एवं शांत प्रतियोगिता में ही भाग लें और अपने निष्पादन तथा निर्माण को ऊंचाई के शिखर पर ले जाने का अथक प्रयास करें।' अब शिष्य पूरी तरह से संतुष्ट था। अंततः,मैं यही कहना चाहती हूँ कि यदि हम मन, वचन और कर्म- इन तीनों ही स्तरों पर इस कहानी का मूल्यांकन करें, तो भी यह कहानी खरी ही उतरेगी। सब के प्रति पूर्वाग्रह से मुक्त मन वाला व्यक्ति अपने वचनों से कभी भी किसी को आहत करने का दुःसाहस नहीं करता और उसकी यही ऊर्जा उसके पुरुषार्थ के मार्ग की समस्त बाधाओं को हर लेती है। वस्तुतः, हमारे जीवन का सबसे बड़ा 'उत्सव' पुरुषार्थ ही होता है-ऐसा विद्वानों का मत है।

हल करो हीरो बनो

1. निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का क्षेत्रीय संगीत नही है?
(क) आल्हा (ख) होरी
(ग) सोहर (घ) लमन

2. उत्तर प्रदेश का बजट 2024-2025 में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए कितना आवंटन किया गया है?
(क) 10,000 करोड़ (ख) 12,000 करोड़
(ग) 14,000 करोड़ (घ) 16,000 करोड़

3. उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा विकेंद्रीकरण एवं प्रशासनिक सुधार आयोग का गठण कब किया गया?
(क) 1985 (ख) 1995
(ग) 2005 (घ) 2015

4. उन गीतों का नाम बताइए जो राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम का गुणगान करते है?
(क) कजरी (ख) ख्याल
(ग) रसिया (घ) चरकुला

5. पौधे के विकास, वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है?
(क) नाइट्रोजन (ख) फास्फोरस
(ग) पौटेशियम (घ) क्लोरीन

(उत्तर इसी अंक में)

माथापच्ची–19

5	8	9	1					
			3				2	7
			6		4			
8	7					4	9	2
		2				3		
4	9	3					7	6
			4		8			
2	1				3			
					1	9	4	5

नियम : प्रत्येक पंक्ति में 1 से 9 तक अंक भरे जाने आवश्यक है, इनका क्रमवार होना आवश्यक नहीं है। आड़ी एवं खड़ी पंक्ति में एवं 3X3 के वर्ग में अंक की पुनरावृत्ति न हो, पहले से मौजूद अंकों को आप हटा नहीं सकते। उत्तर अगले अंक में

माथापच्ची 18 का हल

1	4	9	7	6	3	8	2	5
3	7	2	5	8	4	1	6	9
8	6	5	1	9	2	7	3	4
5	2	3	8	4	9	6	7	1
4	8	1	6	7	5	3	9	2
7	9	6	2	3	1	4	5	8
2	3	4	9	1	6	5	8	7
9	1	8	3	5	7	2	4	6
6	5	7	4	2	8	9	1	3

मार लो मुस्की

डॉक्टर चिंटू से- चश्मा किसके लिए बनवाना है?
चिंटू- जी, मास्टर जी के लिए.
डॉक्टर- पर ऐसा क्यों?
चिंटू- क्योंकि मास्टर जी को मैं हमेशा गधा ही नजर आता हू...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

टकला अपने बीवी से पूछता है- कैसा लग रहा हूं
बीवी- अजी छोड़ो भी
टकला- अरे बता ना
बीवी- अब मैं क्या बताऊं
टकला- अरे बता भी तुझे मेरी कसम
बीवी - ऐसे लग रहे हो जैसे फटे हुए मौजे से अंगूठा बाहर निकल आया हो।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

कोयल और कौवा आपस में बातचीत कर रहे थे.
कोयल- भाई, तुमने अब तक शादी क्यों नहीं की?
कौवा- बहन! बिना शादी के ही जिंदगी में इतनी कांव-कांव है, शादी कर लूंगा तो पता नहीं क्या होगा?

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

क्रिकेट का शौकीन पति
पत्नी- पूरा दिन बस क्रिकेट, क्रिकेट, क्रिकेट
मैं घर छोड़कर जा रही हूं
पति (कमेंट्री करते हुए)- पहली बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

बॉयफ्रेंड- क्या तुम जानती हो कि संगीत में इतनी शक्ति होती है कि पानी गरम हो सकता है
गर्लफ्रेंड- हां जरूर, क्यों नहीं
जब तुम्हारा गाना सुनकर मेरा खून खौल सकता है, तो पानी क्यों नहीं...

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

गप्पू , डॉक्टर से : क्या आप बिना दर्द किए भी दांत निकाल लेते हो?
डॉक्टर : नहीं तो !
गप्पू : मैं निकाल लेता हूं!
डॉक्टर : कैसे?
गप्पू : ही ही ही ही हा हा हा...

पति और पत्नी एक कुएं के पास गए, जहां सिक्का डालने से मन की मुराद पूरी हो जाती थी।
पहले पति ने सिक्का डाला, फिर पत्नी जैसे ही सिक्का डालने गई तो पैर फिसल गया और वो कुएं में गिर गई।
पति की आंखों में आंसू आ गए, ऊपर देखते हुए बोला - हे भगवान, इतनी जल्दी सुन ली।

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

संजू (बंटी से)- आज मैंने अपनी पत्नी को वॉचमैन के साथ पिक्चर देखने जाने का प्लान बनाते हुए सुना
बंटी- तो फिर तुम उनके पीछे नहीं गए?
संजू- नहीं यार, दर... दरअसल वह पिक्चर मेरी देखी हुई थी..

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

मां ने रानी से कहा - बेटी, लैंप जला दो...! कुछ देर बाद बेटी को पास आते देख मां ने पूछा - बेटी, लैंप जला दिया...?
रानी बोली - हां मां, तुमने जब कहा था, तभी चूल्हे में डाल दिया था, अब तक पूरा जल भी गया होगा...!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

भिखारी (महिला से)- भगवान के नाम पर कुछ दे दो
महिला- मेरे पास कुछ नहीं है
भिखारी- बस 5 रुपये का सवाल है
महिला- हां पूछो, क्या पता मुझे आता हो!

▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶ ▶▶

पति घर में शराब पीकर आया, तो पत्नी को गुस्सा आ गया।
गुस्से में पत्नी बोली- आज फिर शराब पी ली, टाइम क्या हुआ है?
पति ने जवाब दिया- 12 में 5 कम
पत्नी ने कहा- देखा शराब पीने का नतीजा, अभी 7 बजे हैं और तुम्हें 12 में 5 कम नजर आ रहा है।
पति बोला- तो 12 में 5 कम कितना होता है? अब बताओ शराब किसने पी रखी है!

राहुल-प्रियंका का ग्लैमर, मीडिया की बेवकूफी या साजिश

संजय सक्सेना

कांग्रेस का गांधी परिवार भारतीय राजनीति का एक ऐसा रहस्य बना हुआ है जो दशकों से अनसुलझा है। आश्चर्य होता है कि गांधी परिवार की नाकामियां साफ नजर आने के बावजूद कांग्रेसी नेता उनके आगे नतमस्तक क्यों बने रहते हैं? नेहरू युग से शुरू हुआ यह सिलसिला राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा तक पहुंचा है, जहां परिवार के दोनों वारिसों का योगदान कांग्रेस के पतन में कहीं ज्यादा साफ दिखता है। 2014 और 2019 के लोकसभा चुनावों में पार्टी का बुरा हाल रहा सीटें घटकर महज 44 और फिर 52 रह गईं। फिर भी कांग्रेसी नेता चुपचाप उनके पीछे लाइन लगाए खड़े हैं। यह वफादारी समझ में आ सकती है, क्योंकि उनके पास परिवार से जुड़े हित, पुरानी दोस्तियां और राजनीतिक उत्तराधिकार की मजबूरियां हैं। लेकिन मीडिया, खासकर इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स का यह आकर्षण क्या है? राहुल-प्रियंका की हर छोटी-मोटी गतिविधि, हर बयान को ब्रेकिंग न्यूज़ बना देना? यह ग्लैमर कहां से आता है, जब तथ्य इनकी राजनीतिक साख को धूल चटाते हैं? कांग्रेसियों की स्थिति तो कुछ हद तक सहानुभूतिपूर्ण लग सकती है। नेहरू-इंदिरा राज की चमक अभी भी उनके दिमाग में बसी है। गांधी परिवार को पार्टी का सूत्रधार मानना उनकी रणनीति का हिस्सा है। राहुल के अध्यक्ष बनने पर भी पार्टी ने हार स्वीकार की, लेकिन विद्रोह नहीं किया। प्रियंका की उत्तर प्रदेश में एंट्री को मास्टर स्ट्रोक समझा गया, पर 2022 विधानसभा चुनावों में कांग्रेस का सूपड़ा साफ हो गया। कांग्रेसी जानते हैं कि गांधी परिवार के बिना पार्टी का कोई भविष्य नहीं है। कांग्रेसियों की मजबूरी है उनको गांधी परिवार से इतर वैकल्पिक चेहरा न होने से डर लगता है। लेकिन मीडिया की यह भक्ति कहां से उपजी? क्या यह नेहरूवादी विरासत का भूत है या कुछ और? राहुल गांधी पर पप्पू का तमगा चिपक चुका है। संसद में नारे लगाना, विदेश यात्राओं पर बयानबाजी, और चुनावी हार के बाद भगोड़ा बन जाना ये सब तथ्य हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन में उनकी भूमिका रही, लेकिन कांग्रेस फिर 99 सीटों पर सिमट गई। प्रियंका वाड्रा की कहानी भी कमाल की है। पूर्वी उत्तर प्रदेश प्रभारी बनीं, लेकिन योगी आदित्यनाथ के सामने धराशायी। वायनाड उपचुनाव में राहुल की हार, प्रियंका की सड़क यात्राएं ये मीडिया में सब सुर्खियां बटोरती रहीं। मीडिया इन्हें मोदी-योगी जैसे दिग्गजों से तौलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से केंद्र तक का सफर तय किया, योगी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकास के पथ पर ला खड़ा किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी को मजबूत बनाया, मायावती ने दलित राजनीति को नई ऊंचाई दी, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को युवा चेहरा दिया। इनकी साख तथ्यों पर टिकी है विकास, सुशासन, जीत। परंतु राहुल-प्रियंका की साख? सिर्फ वंशवाद और हार की कहानियां। फिर भी टीवी चैनल्स पर राहुल का हर ट्वीट ब्रेकिंग न्यूज़। प्रियंका का कोई सड़क शो तो जैसे चुनाव जीत लिया। क्यों? तथ्य बताते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा वामपंथी विचारधारा से प्रभावित है। नेहरू युग में प्रेस को संरक्षण मिला, आज भी वही पुराना कनेक्शन काम करता है। टीआरपी की होड़ में विवादास्पद बयान बिकते हैं। राहुल का ''चौकीदार चोर है'' या प्रियंका का मोदी पर हमला ये चटपटे हैं। मोदी का कोई भाषण? बोरिंग विकास गाथा। योगी का बुलडोजर एक्शन? तो सांप्रदायिक करार दो। लेकिन गांधी परिवार को ग्लैमर का चोला पहनाना क्यों? शायद इसलिए कि वे विपक्ष के प्रतीक हैं। विपक्ष कमजोर हो तो सरकार की जवाबदेही कम। मीडिया जानबूझकर गांधी भाइयों-बहनों को फुल कवरेज देता है ताकि विपक्ष का भ्रम बना रहे।तथ्यों पर गौर करें। 2019 चुनाव में राहुल की अमेठी हार ने परिवार की राजनीतिक पूंजी को चकनाचूर कर दिया। प्रियंका को सोनिया ने मैदान में उतारा, लेकिन परिणाम? जीरो। 2023 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस हारी, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा बेकार। इसके उलट मोदी ने 2014 से तीन चुनाव जीते, योगी ने 2022 में 273 सीटें दिलाईं। अखिलेश ने 37 लोकसभा सीटें झटकीं। ये नेता काम से पहचाने जाते हैं, न कि वंश से। मीडिया की तुलना गलत क्यों? क्योंकि राहुल को युवा चेहरा कहना मजाक है। उम्र में अखिलेश से बड़े, पर उपलब्धि शून्य। प्रियंका को महिला सशक्तिकरण का प्रतीक बताया जाता है? जबकि पार्टी में महिलाओं की भागीदारी घट रही है। गांधी खानदान के प्रति यह ग्लैमर का भ्रम क्यों टूटता नहीं? सोशल मीडिया पर गांधी परिवार को ट्रोल किया जाता है, लेकिन मुख्यधारा मीडिया चुप। क्योंकि चैनल्स के मालिकों के हित जुड़े हैं। पुरानी कांग्रेसी सरकारों से लाभ मिला। आज भी विपक्षी ध्रुवीकरण से फायदा। राहुल का अमेरिका दौरा जहां वे ''डेमोक्रेसी खतरे में'' बोलते हैं, वहां मोदी की जी-20 सफलता दब जाती है। प्रियंका का हर बयान महत्वपूर्ण बन जाता है।

तथ्य कहते हैं इनकी लोकप्रियता घटी है। सर्वे दिखाते हैं मोदी-योगी टॉप पर। फिर भी मीडिया गांधी परिवार को हीरो बनाता है। क्यों? शायद डर से। सरकार का पक्ष लेने पर लाइसेंस रद्द का भय। विपक्ष को जिंदा रखना सुरक्षित लगता है। खैर, कांग्रेसियों की मजबूरी समझ आती है, वे पार्टी बचाने के लिए झुकते हैं। लेकिन मीडिया का यह आग्रह तथ्यों का अपमान है। जब तक यह जारी रहेगा, राजनीति का संतुलन बना रहेगा, पर लोकतंत्र कमजोर होगा। राहुल-प्रियंका को सच्चाई का आईना दिखाना होगा। उनकी तुलना उन नेताओं से न करें जिन्होंने मेहनत से इतिहास रचा। वरना यह ग्लैमर का बुलबुला फूटेगा ही। समय आ गया है कि मीडिया तथ्यों पर खड़ा हो, वंशवाद के आगे न झुके।

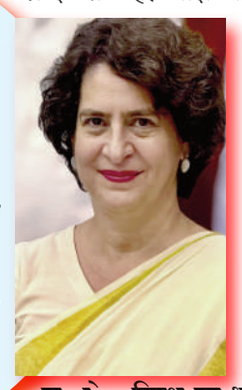

वायनाड

उपचुनाव में राहुल की हार, प्रियंका की सड़क यात्राएं ये मीडिया में सब सुर्खियां बटोरती रहीं। मीडिया इन्हें मोदी-योगी जैसे दिग्गजों से तौलता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात से केंद्र तक का सफर तय किया, योगी ने उत्तर प्रदेश को अपराध मुक्त और विकास के पथ पर ला खड़ा किया। ममता बनर्जी ने बंगाल में टीएमसी को मजबूत बनाया, मायावती ने दलित राजनीति को नई ऊंचाई दी, अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी को युवा चेहरा दिया। इनकी साख तथ्यों पर टिकी है विकास, सुशासन, जीत। परंतु राहुल-प्रियंका की साख? सिर्फ वंशवाद और हार की कहानियां।

बिहार के 38 जिलों में राशन कार्ड से कटेंगे 52 लाख से अधिक लोगों के नाम

- गलत या बिना आधार वालों पर कार्रवाई

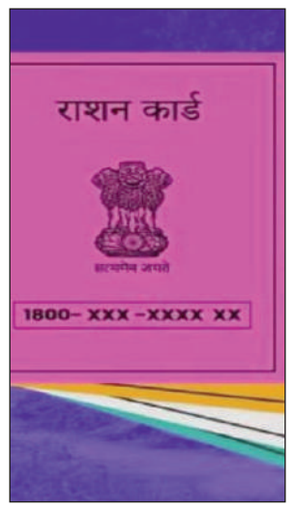

निज संवाददाता : बिहार के सभी 38 जिलों में करीब 52.22 लाख लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जा सकते हैं। दरअसल खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने यह आदेश आधार कार्ड न होने या गलत होने के कारण वेरिफिकेशन रिजेक्ट होने के बाद दिया। बताया गया है कि अब तक राज्य में 5.92 करोड़ राशन कार्ड धारकों का आधार वेरिफिकेशन किया जा चुका है। जबकि कुल 6.74 करोड़ पीडीएस लाभुकों की आधार सीडिंग अभी बाकी है। जिन लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए जाएंगे, उन्हें सस्ते या मुफ्त पीडीएस दुकानों से अनाज नहीं मिलेगा। जिलावार जानकारी के अनुसार, पटना में 27.3 लाख, समस्तीपुर 25.7 लाख, मुजफ्फरपुर 30.4 लाख, सीतामढ़ी 21.0 लाख, दरभंगा 24.7 लाख, नालंदा 15.3 लाख, पूर्वी चंपारण 28.6 लाख, मधुबनी 26.9 लाख, पश्चिम चंपारण 23.8 लाख और वैशाली 18.9 लाख वेरिफिकेशन एक्सेप्ट हुए। जबकि पटना में 2.96 लाख, समस्तीपुर 1.40 लाख, दरभंगा 2.64 लाख, मधुबनी 1.98 लाख, नालंदा 2.29 लाख, पूर्वी चंपारण 2.21 लाख, मुजफ्फरपुर 1.79 लाख, सीतामढ़ी 98.7 हजार, पश्चिम चंपारण 2.06 लाख और वैशाली 2.43 लाख लोगों का वेरिफिकेशन रिजेक्ट हुआ। मालूम हो कि बिहार सरकार ने आम लोगों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन कर दी है। इच्छुक आवेदक घर बैठे ... वेबसाइट पर जाकर आसानी से राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वित्त मंत्री के सामनें होंगी कई चुनौतियां

1 फरवरी को पेश होगा केंद्रीय बजट

निज संवाददाता : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को वित्त वर्ष 2026-27 का केंद्रीय बजट पेश करेंगी। इस बार बजट में उनके सामने कई अहम चुनौतियां होंगी, जिनमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का विस्तार और आम लोगों को रियायती दरों पर इलाज उपलब्ध कराना प्रमुख मुद्दे रह सकते हैं। विकसित देशों की तुलना में भारत सहित अधिकांश विकासशील देशों में स्वास्थ्य पर सरकारी खर्च अभी भी काफी कम है, जबकि बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं किसी भी मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद होती हैं। विश्व बैंक की 2022 की रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि स्वास्थ्य पर खर्च के मामले में देशों के बीच बड़ा अंतर है। अमेरिका अपनी जीडीपी का लगभग 17 से 18 फीसद स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च करता है, जो प्रति व्यक्ति करीब 12 से 13 हजार डॉलर बैठता है। हालांकि, वहां सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था कमजोर है और निजी क्षेत्र पर निर्भरता ज्यादा है। जापान अपनी जीडीपी का 10 से 11 फीसद मेडिकल सेक्टर पर खर्च करता है, जिससे प्रति व्यक्ति खर्च 700 से 900 डॉलर तक पहुंचता है। इसके मुकाबले भारत स्वास्थ्य पर जीडीपी का केवल 3 से 4 फीसद खर्च करता है और प्रति व्यक्ति खर्च महज 100 से 200 डॉलर के बीच है। हालांकि, आयुष्मान भारत जैसी योजनाओं से स्थिति में धीरे-धीरे सुधार की कोशिश की जा रही है। पिछले बजटों की बात करें तो सरकार ने डिजिटल हेल्थ, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, घरेलू उत्पादन और सस्ती दवाओं पर फोकस बढ़ाया है। वित्त वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए करीब 1 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया गया था, जो पिछले वर्ष से लगभग 11 फीसद अधिक था। इसमें आयुष्मान भारत के विस्तार, कैंसर की दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट, नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन व एम्स जैसे संस्थानों के लिए अतिरिक्त फंड की घोषणा की गई थी। मेडिकल बजट 2026-27 को लेकर विशेषज्ञों का मानना है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का हिस्सा और बढ़ाया जाना चाहिए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शरद अग्रवाल के अनुसार, बजट में स्वास्थ्य खर्च को अलग-अलग मदों में स्पष्ट रूप से दिखाया जाना चाहिए, ताकि यह पता चल सके कि कितना खर्च इंफ्रास्ट्रक्चर विकास पर हो रहा है और कितना वेतन व अन्य प्रशासनिक मदों में जा रहा है। उनका कहना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर खास ध्यान देना बेहद जरूरी है। डॉ. अग्रवाल ने यह भी सुझाव दिया कि दवाओं, मेडिकल इक्विपमेंट और सर्जिकल उत्पादों को जीएसटी के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि इलाज की लागत कम हो सके। इसके साथ ही मेडिकल उपकरणों पर लगने वाले सीमा शुल्क में भी राहत दी जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि जैसे जीवन बीमा पर टैक्स छूट मिलती है, उसी तरह हेल्थ इंश्योरेंस को भी टैक्स में अतिरिक्त छूट देकर बढ़ावा दिया जाना चाहिए। उनका मानना है कि कोविड-19 के बाद देश में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी दूर-दराज के इलाकों में काफी काम किया जाना बाकी है। एंबुलेंस सेवाओं, ऑक्सीजन प्लांट, सोलर पैनल, जनरेटर, ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर और अन्य जरूरी उपकरणों की गुणवत्ता और उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत है। कोविड काल में लगाए गए कई वेंटिलेटर आज खराब पड़े हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता ठीक नहीं थी। इसलिए जरूरी है कि स्वास्थ्य बजट के तहत होने वाले खर्च की सख्त निगरानी हो और एक स्वतंत्र, निष्पक्ष संस्था इसके क्रियान्वयन और गुणवत्ता की जांच कर सके।

सुप्रीम कोर्ट का राज्यों को बड़ा आदेश

- 'स्कूलों में मुफ्त मिले सैनेटरी पैड, नहीं तो मान्यता होगी रद्द'

निज संवाददाता : सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को मुफ्त में बायोडिग्रेडेबल सैनेटरी पैड दिए जाएं। शीर्ष अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मेंस्ट्रुअल हेल्थ यानी मासिक धर्म स्वास्थ्य के अधिकार के तहत संविधान में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा है।

स्कूली बच्चियों के स्वास्थ्य से जुड़े आदेश पर अदालत ने कहा है कि अगर सरकारें स्कूली छात्राओं को टॉयलेट और मुफ्त सैनेटरी पैड देने में फेल होती हैं, तो उन्हें भी जवाबदेह ठहराया जाएगा। वरिष्ठ न्यायाधीश जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने कक्षा 6 से 12 तक की छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे देश में लागू करने पर यह आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अगर प्राइवेट स्कूल लड़कियों और लड़कों के लिए अलग-अलग शौचालय और सैनेटरी पैड देने में फेल होते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। कोर्ट ने कहा-मासिक धर्म स्वास्थ्य का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा है। अगर प्राइवेट स्कूल ये सुविधाएं देने में विफल रहते हैं, तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी के साथ अदालत ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से सभी स्कूलों में दिव्यांगों के लिए अनुकूल शौचालय उपलब्ध कराने के लिए भी कहा है। वहीं सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्कूलों में महिला और पुरुष छात्रों के लिए अलग-अलग शौचालय सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने 10 दिसंबर, 2024 को जया ठाकुर की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें कक्षा 6 से 12 तक की किशोर छात्राओं के लिए सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में केंद्र सरकार की स्कूल जाने वाली लड़कियों के लिए मासिक धर्म स्वच्छता नीति को पूरे भारत में लागू करने की मांग की गई।

कोलकाता मेट्रो में फिर से शुरू हुई रिटर्न टिकट सेवा

- पुराने सिस्टम को ट्रायल बेसिस पर लाया गया वापस

निज संवाददाता : कोलकाता मेट्रो में ट्रायल बेसिस (प्रायोगिक) के तौर पर रिटर्न टिकट फिर से शुरू किए गए हैं। पहले जब पेपर टिकट मिलते थे, तो यात्रियों को मेट्रो में रिटर्न टिकट की सुविधा मिलती थी। लेकिन, जब से टोकन सिस्टम शुरू हुआ है, यह सुविधा अब नहीं मिल रही है। मेट्रो अधिकारियों ने शनिवार से एक्सपेरिमेंट के तौर पर रिटर्न टिकट शुरू किए हैं। इससे यात्रियों को बार-बार टिकट काउंटर पर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। वे एक ही बार में अपनी यात्रा के टिकट खरीद सकेंगे।कोलकाता मेट्रो में टोकन टिकट सिस्टम 1 अगस्त, 2011 से शुरू किया गया था। पेपर टिकट में रिटर्न टिकट की सुविधा तो थी, लेकिन टोकन में यह मुमकिन नहीं था। इसलिए वह सर्विस बंद कर दी गई थी। रिटर्न सर्विस उन लोगों के लिए ज़रूरी है जो रोज मेट्रो से जाते हैं और मेट्रो में वापस आते हैं। अब क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट शुरू होने से एक नई रिटर्न सर्विस शुरू की गई है। इससे उम्मीद है कि टिकट काउंटर पर मेट्रो अधिकारियों पर दबाव भी कुछ कम होगा। मेट्रो के चीफ पब्लिक रिलेशन्स ऑफिसर (पीआरओ) एसएस कन्नन ने कहा-हमने ट्रायल बेसिस पर रिटर्न टिकट शुरू किए हैं। टिकट खरीदने के बाद, इसे एंट्री गेट पर स्कैन करके यात्रा के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरह, वापस आते समय उन्हें बुकिंग काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। वे इसे स्कैन करके सीधे जा सकते हैं।मालूम हो कि कोलकाता मेट्रो के टिकट काउंटरों पर क्यूआर कोड वाले पेपर टिकट 2025 से उपलब्ध हैं। तभी से, अधिकारी रिटर्न सर्विस शुरू करने के बारे में सोच रहे थे। आखिरकार, इसे लॉन्च किया गया। यह सुविधा ट्रेनों के मामले में उपलब्ध है।

हालांकि यह सर्विस अभी मेट्रो में ट्रायल बेसिस पर चलाई जा रही है। अगर मेट्रो अधिकारियों को लगता है कि रिटर्न टिकट की मांग है, तो इस सर्विस को परमानेंट किया जा सकता है।गौरतलब है कि मेट्रो में स्टाफ की कमी के कारण, व्यस्त समय में टिकट काउंटरों पर अतिरिक्त दबाव होता है। यात्रियों को लंबी लाइनों में खड़ा होना पड़ता है। अगर इनमें से कुछ यात्री रिटर्न टिकट खरीद लेते हैं, तो उन्हें एक से ज़्यादा बार काउंटर पर नहीं जाना पड़ेगा। इससे काउंटरों पर लगने वाली लाइनें कुछ हद तक कम हो जाएंगी। इसके अलावा, जब से अलग-अलग रूट पर कनेक्टेड मेट्रो सर्विस शुरू हुई हैं, किराए को लेकर दिक्कत आ रही है। जो लोग ऑनलाइन ट्रांज़ैक्शन नहीं जानते, वे कैश में टिकट खरीदते हैं। मेट्रो कर्मचारियों को रिटेल प्राइस रिफंड करने में दिक्कत होती है। अगर रिटर्न काट लिया जाए, तो यह दिक्कत भी कुछ हद तक हल हो सकती है।

बिना बैंड, बाजा, बाराती के सज रही हैं नकली शादी की थीम पार्टियां

- कोलकाता में भी आ गया ग्लोबल क्रेज

निज संवाददाता : फेक वेडिंग थीम (नकली शादी की थीम) पार्टियों का ग्लोबल क्रेज़ कोलकाता में आ गया है, जिससे बड़ी भारतीय शादी एक मज़ेदार, बिना किसी कमिटमेंट वाली नाइट आउट बन गई है। दुनिया भर में, पार्टी करने वाले युवा ऐसे इमर्सिव इवेंट्स (निमग्न इवेंट्स) में आ रहे हैं जो शादी की मस्ती, फैशन और उथल-पुथल को फिर से दिखाते हैं। अब, शहर की नाइटलाइफ़ भी इस ट्रेंड का खुले दिल से स्वागत कर रही है।फेक वेडिंग पार्टी क्या है?फेक वेडिंग असल में एक थीम वाली पार्टी होती हैबिना किसी दिखावटीपन के एक बड़ी इंडियन शादी। सोचिए लहंगा, शेरवानी, ढोल, फूलों की बारिश, मज़ेदार रस्में और भरा हुआ डांस फ्लोर, लेकिन बिना किसी असली कसम या परेशान करने वाले रिश्तेदारों के। यह एक बहुत बड़ी बनावटी शादी है जहां हर कोई सिर्फ़ मज़ेदार हिस्सों के लिए आता है।इस ट्रेंड को जेन-जी और यंग वर्किंग प्रोफेशनल्स (युवा कामकाजी पेशेवर) में सबसे ज़्यादा फ़ैन मिले हैं, जिन्हें शादियों की खूबसूरती और एनर्जी पसंद है, लेकिन उनसे जुड़ी जांच-पड़ताल या गंभीरता नहीं।गौरतलब है कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु और गोवा जैसे शहरों में, नकली शादियां पहले से ही नाइटलाइफ़ का एक अहम हिस्सा बन गई हैं, जिन्हें अक्सर ऐसे क्लब होस्ट करते हैं जो बोल्ड, एक्सपीरिएंशियल इवेंट्स (अनुभवात्मक समारोह) के लिए जाने जाते हैं। ये समारोह भीड़ को खींचते हैं जो ओवर-द-टॉप आउटफिट्स, ड्रामैटिक एंट्रीज़, क्यूरेटेड फ़ोटो-ऑप्स और ऐसी जगह की तलाश में होते हैं जहां वे बिना किसी जजमेंट के आराम कर सकें।कोलकाता के हालिया एडिशन इसी मूड को दिखाते हैं, जिसमें शामिल होने वाले लोग रात को एक ग्लैमरस एस्केप की तरह लेते हैं जहां सब कुछ बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया जाता है और किसी भी चीज़ को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता है।इस साल की शुरुआत में, तंत्रा एट द पार्क ने जब वी मीट के साथ अपना वर्ज़न होस्ट किया, जो एक थीम वाली रात थी जिसमें पूरा हाउस भरा हुआ था। क्लब एक वाइब्रेंट वेडिंग वेन्यू (जीवंत विवाह स्थल) जैसा था और मेहमान लहंगा, शेरवानी और सजावटी ज्वेलरी पहनकर आए थे। यहां हल्दी सेरेमनी जैसी नकली रस्में थीं और ढोल ने रात का मूड बनाया। रेजिडेंट डीजे ने 'तेनु लेके' और 'साडी गली' जैसे पसंदीदा गानों से भीड़ को बांधे रखा। क्लब के मैनेजमेंट ने कहा कि उन्हें ज़बरदस्त रिस्पॉन्स मिला। द पार्क कोलकाता के जनरल मैनेजर प्रमोद भंडारी ने कहा-हमें पता था कि यह कॉन्सेप्ट लोगों को पसंद आएगा, लेकिन लोगों की भीड़ उम्मीद से ज़्यादा थी। ग्लैमर और बेफ़िक्र सेलिब्रेशन के मिक्स के कारण इस रात रेगुलर क्लबर्स (नियमित क्लबों में जाने वाले) ने काफ़ी शिरकत की।बड़ी बात यह कि कई युवाओं के लिए, ये रातें बिना किसी जजमेंट के शादियों के मज़ेदार हिस्सों का मज़ा लेने का मौका देती हैं। अस्मिता घोष, एक आईटी प्रोफ़ेशनल और जेन-जी पार्टी-गोअर, ने कहा-मैं इंडियन शादियों की बहुत बड़ी फ़ैन हूं। मुझे अपने खूबसूरत लहंगे पहनने को मिलते हैं, मुझे अच्छा खाना खाने को मिलता है और मैं इसके वाइब (अनुभूति) का मज़ा लेती हूं। लेकिन ये पार्टियां भीड़ के मामले में सबसे अलग होती हैं। असली शादियों में, आपके कुछ जानने वाले रिश्तेदार होते हैं जो जज करते हैं। लेकिन इन पार्टियों में, यह सच में मज़ेदार होता है।बताया जाता है कि अगली बड़ी फ़ेक वेडिंग पार्टी 22 नवंबर को द ललित ग्रेट ईस्टर्न कोलकाता में किट्टी सु के एशिया टेकओवर 2.0 एक्स प्योर लव की फ़ेक वेडिंग के साथ होने वाली है।

बिजनेस के लिए सिकुड़ रहा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स

मछली पालन से तालाबों को मिल रहा बढ़ावा

निज संवाददाता : ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स का छोटे बिज़नेस और रियल एस्टेट के लिए कब्ज़ा किया जाना जगजाहिर है। लेकिन वेटलैंड्स के कुछ हिस्सों में, मछली पालन से ज़्यादा मुनाफ़े की वजह से ज़मीन को पानी की जगहों में भी बदला जा रहा है। यहां के रहने वालों ने कहा-इन हिस्सों में खेती की ज़मीन पर साल में एक से ज़्यादा फ़सल नहीं होती, जबकि मछली पालन में साल में तीन से चार बार फ़सल हो सकती है।स्थानीय कोऑपरेटिव और सरकारी अधिकारियों ने कहा कि जैसे पानी की जगहों के कुछ हिस्सों को अक्सर ज़मीन बनाने के लिए भर दिया जाता है, वैसे ही इसका उल्टा भी हो रहा है। मछुआरों की कोऑपरेटिव के एक सदस्य ने कहा कि पिछले दो दशकों में, खेती की बड़ी ज़मीन चुपचाप मछली पालन के लिए बदल दी गई है, जिससे धान की खेती के लिए शायद ही कोई ज़मीन बची है।कोलकाता से नज़दीकी होने की वजह से इन पानी की जगहों में पाली जाने वाली मछलियों के लिए एक तैयार बाज़ार मिल गया है।ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स मैनेजमेंट अथॉरिटी की वेबसाइट के मुताबिक, नोटिफ़ाइड वेटलैंड्स एरिया में 254 सीवेज से चलने वाली मछली पालन हैं। लेकिन, लोगों, मछुआरों की कोऑपरेटिव और अधिकारियों से बातचीत से पता चलता है कि असल संख्या काफी ज़्यादा है।खेयादाहा ग्राम पंचायत इलाके की एक कोऑपरेटिव, तरुणी कांता बाग फिश प्रोडक्शन ग्रुप के एक सदस्य ने कहा-हम करीब 25 सदस्यों वाली एक कोऑपरेटिव चलाते हैं। हमारी भेरी करीब 30 बीघा की है। मछली पालन से होने वाली इनकम धान की खेती से होने वाली कमाई से तीन गुना से भी ज़्यादा है।उन्होंने कहा-करीब दो दशक पहले, यहां कई ज़मीनों पर धान की खेती होती थी। अब, मैं मुश्किल से ही किसी को धान उगाते हुए देखता हूँ। धान से यहाँ साल में एक ही फसल मिलती है। मछली पालन से साल के आखिर में तालाबों की सफाई में लगने वाले समय को ध्यान में रखने के बाद भी, साल में तीन या चार बार मछली पालन हो पाता है।इनमें से ज़्यादातर बदलाव राज्य सरकार की इजाज़त के बिना किए गए थे। दक्षिण 24-परगना डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के एक पुराने सीनियर अधिकारी ने कहा कि कुछ साल पहले, सरकार ने ज़मीन पर बड़े पैमाने पर बदलाव होते देखकर, बास्तु (घर और खेती की ज़मीन नहीं) के तौर पर क्लासिफ़ाइड ज़मीन को वॉटर बॉडी में बदलने की इजाज़त दी थी।अधिकारी ने कहा-राज्य ने सोचा था कि इन बदलावों को रेगुलर करके वह कुछ रेवेन्यू कमा सकता है, लेकिन कमाई बहुत कम रही है।ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स में सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली मछलियों की किस्मों में रोहू, कतला, तिलापिया और सिल्वर कार्प शामिल हैं। यह प्रोड्यूस गरियाहाट, न्यू मार्केट, बालीगंज रेलवे स्टेशन के बाहर के बाज़ार और कालीघाट जैसे मार्केट में सप्लाई किया जाता है।वेटलैंड्स के पास मौजूद होलसेल मार्केट रिटेल हब तक आसान पहुंच पक्का करने में मदद करते हैं। एक कोऑपरेटिव मेंबर ने कहा-चौभागा, बंटाला, गंगाजोर और गरिया रेलवे स्टेशन के पास होलसेल फिश मार्केट हैं। वेटलैंड्स अथॉरिटी के एक मेंबर ने कहा कि सर्वे से पता चलता है कि नोटिफाइड वेटलैंड्स में फ्रेशवॉटर फिशरीज़ का एरिया पिछले कुछ सालों में लगभग दोगुना हो गया है। मेंबर ने कहा-ईस्ट कोलकाता वेटलैंड्स के तौर पर नोटिफाइड 12,500 हेक्टेयर में से, जब 2006 में वेटलैंड्स को प्रोटेक्टेड एरिया घोषित किया गया था, तब वॉटर बॉडीज़ शुरू में लगभग 3,500 हेक्टेयर में फैली हुई थीं। यह आंकड़ा अब बढ़कर लगभग 6,000 हेक्टेयर हो गया है। वॉटर बॉडीज़ के अलावा, नोटिफाइड वेटलैंड्स में खेती लायक ज़मीन, बंजर ज़मीन और गांव और शहर की बस्तियां भी शामिल हैं। हालांकि कोलकाता, साल्ट लेक और न्यू टाउन के पास, वेटलैंड्स कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के कई वार्डों के साथ-साथ साउथ और नॉर्थ 24-परगना जिलों के पंचायत एरिया में फैले हुए हैं। सोनारपुर पंचायत समिति के सभापति बलाई चंद्र बारिक ने कहा, ''नोटिफाइड वेटलैंड्स में खेयादादा और , और साउथ 24-परगना में प्रतापनगर ग्राम पंचायतें शामिल हैं। कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि इन बदलावों से पर्यावरण को फ़ायदा हो सकता है। एक एनवायरनमेंटल साइंटिस्ट ने कहा-पानी की जगहों में बढ़ोतरी से तेज़, कम समय की बारिश को मैनेज करने में मदद मिल सकती है, जो क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़्यादा बार होने की संभावना है। ये पानी की जगहें कार्बन सिंक का भी काम कर सकती हैं।

सोशल मीडिया के ज़माने में छात्रों के लिए नई पहल

स्कूल के अंदर चल रही है 'विवेक एक्सप्रेस'

निज संवाददाता : लोगों में ज़मीर की भावना जगाने के लिए, क्लासरूम को रीडिज़ाइन करके ट्रेन का रूप दिया गया है। इसका नाम विवेक एक्सप्रेस रखा गया है। सोशल मीडिया के ज़माने में, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए, पूर्व मेदिनीपुर के कांथी में नयापुत सुधीर कुमार हाई स्कूल ने क्लासरूम को ट्रेन में बदलने का नया आइडिया अपनाकर एक मिसाल कायम की है। ट्रेन के तीन डिब्बों पर किताबों की 42 तस्वीरें पेंट की गई हैं। जब आप इसे देखते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे ट्रेन एक पूरी बुकशेल्फ़ हो। स्कूल की विवेक एक्सप्रेस बिल्डिंग का हाल ही में उद्घाटन हुआ था। तब से, इसने हर तरह के लोगों का ध्यान खींचा है। स्कूल अधिकारियों का दावा है कि सोशल मीडिया के आकर्षण के कारण, स्टूडेंट्स धीरे-धीरे किताबों की दुनिया को भूल रहे हैं। उनमें नई और अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ने की आदत नहीं बन रही है। नतीजतन, छात्रों की बेसिक सोच विकसित नहीं हो रही है। और अगर बेसिक सोच विकसित नहीं होगी, तो न तो ज़मीर विकसित होगा और न ही अच्छे-बुरे का फैसला। स्कूल के हेडमास्टर बसंत कुमार घोराई ने कहा-किताबों और स्कूल में दिलचस्पी बढ़ाने के लिए यह पहल की गई है। अब लोगों की ज़मीर कम हो रही है। स्टूडेंट्स को अपनी ज़मीर या मेंटल डेवलपमेंट के लिए अलग-अलग तरह की किताबें पढ़ने की ज़रूरत है। अगर वे सोशल मीडिया पर फोकस करेंगे, तो यह कभी मुमकिन नहीं होगा। सिर्फ़ किताबें ही लोगों में ज़मीर और बेसिक सोच पैदा कर सकती हैं। और ऐसी पहल इसलिए की गई है ताकि कम उम्र से ही किताबें पढ़ने की आदत डाली जा सके।

बसंत पंचमी के साथ शुरू हो गई ब्रज की होली

40 दिनों तक चलेगा रंगों का महोत्सव

निज संवाददाता : ब्रज में 2026 की होली की शुरुआत बसंत पंचमी के साथ हो चुकी है, जो भगवान कृष्ण की पवित्र भूमि पर मनाए जाने वाले 40 दिवसीय रंगोत्सव का प्रतीक है। वृंदावन, बरसाना, नंदगांव और मथुरा में मनाया जाने वाला यह लंबा होली उत्सव अपनी भक्तिमय रीति-रिवाज, जीवंत परंपराओं और गहरी सांस्कृतियों को जोड़ने के लिए जाना जाता है।राधा रानी और भगवान कृष्ण की अद्भुत लीलाओं से जुड़ा ब्रज क्षेत्र 40 दिनों तक रंगों और भक्ति में डूबा रहने वाला है। मंदिर के आंगन से लेकर पतली गलियों तक हर कोने में होली की भावना पारंपरिक रूप से देखने को मिलेगी। 40 दिनों तक ब्रज की होली का गहरा आध्यात्मिक महत्व है, जिसकी शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से होती है। ब्रज में होली नई शुरुआत, भक्ति और खुशी का प्रतीक माना जाता है। इसमें खास रस्मों में से एक है मंदिर के अंदर होली का डंडा लगाना, जो उत्सव के रस्मों की शुरुआत का संकेत है। रंगोत्सव के दौरान, भक्त राधा रानी और भगवान कृष्ण को ताजे फूल से बने रंग और गुलाल चढ़ाए जाते हैं। ब्रज के मंदिरों में फूलों की होली, लट्ठमार होली और लड्डू मार होली जैसे अनोखे उत्सव का भव्य आयोजन किया जाता है, जो आज से नहीं, बल्कि सदियों पुरानी परंपरा है। भक्तों के लिए ब्रज में होली खेलना एक आशीर्वाद का प्रतीक है, पूरा इलाका भक्ति गीतों और कीर्तन से गूंज उठता है, जिससे ब्रज होली भारत के सबसे आध्यात्मिक त्योहारों में से एक बन जाती है। खास बात यह कि एक दिन के होली उत्सव के उलट ब्रज की होली 40 दिनों तक चलती है, जिसमें आस्था, लोकगीत का मिलाजुला त्योहार होता है। हर रस्में राधा और कृष्ण के बीच दिव्य मिलन को दर्शाती हैं, जिससे भक्तों को पवित्र परंपराओं में बताई गई होली का अनुभव प्राप्त करने का दुर्लभ मौका मिलता है। वृंदावन के मंदिरों से लेकर बरसाना की गलियों और नंदगांव के आंगनों तक ब्रज होली 2026 भक्ति, रंग और सांस्कृतिक विरासत की एक बेहतरीन यात्रा का भरोसा दिलाता है।

ब्रज में होली की तिथि

दिनांक	दिन	घटना	स्थान
23 जनवरी 2026	शुक्रवार	(होली का जश्न शुरू)	बांके बिहारी जी मंदिर और सभी ब्रज मंदिर
24 फरवरी 2026	मंगलवार	लड्डू मार होली (फाग निमंत्रण)	श्री जी मंदिर, बरसाना
25 फरवरी 2026	बुधवार	लठमार होली	रंगिली गली, बरसाना
26 फरवरी 2026	गुरुवार	लठमार होली	नंद भवन, नंदगाँव
27 फरवरी 2026	शुक्रवार	रंगभरनी एकादशी/फूलों वाली होली	बांकेबिहारी मंदिर, वृन्दावन
1 मार्च 2026	रविवार	छड़िमर होली	गोकुल
2 मार्च 2026	सोमवार	रमन रेती होली/विधवा होली	गोकुल और वृंदावन
3 मार्च 2026	मंगलवार	होलिका दहन	द्वारकाधीश मंदिर, मथुरा और अन्य मंदिर
4 मार्च 2026	बुधवार	धुलंदी	मथुरा, वृन्दावन, बरसाना, नंदगांव और गोकुल
5 मार्च 2026	गुरुवार	दाऊजी का हुरंगा	मथुरा में दाऊ जी मंदिर

बंगाल एसआईआर में जल्दबाज़ी पर अमर्त्य सेन ने जताई चिंता

कहा-खतरे में पड़ सकती है मतदाताओं की लोकतांत्रिक हिस्सेदारी

निज संवाददाता : नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि बंगाल में मतदाता सूची का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) ''बहुत ज़्यादा जल्दबाज़ी'' में किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी कि इससे लोकतांत्रिक हिस्सेदारी खतरे में पड़ सकती है, खासकर जब विधानसभा चुनाव में कुछ महीने बाकी हैं।92 साल के सेन ने कहा-चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट को यह पक्का करना चाहिए कि किसी भी वयस्क भारतीय नागरिक को वोट देने के लिए क्वालिफ़ाई करने में मुश्किल न हो। सेन एसआईआर की ज़रूरत से सहमत नहीं थे, लेकिन उन्होंने इस प्रोसेस पर सवाल उठाए। सेन ने कहा-इलेक्टोरल रोल का सही समय पर ध्यान से किया गया पूरा रिव्यू एक अच्छा डेमोक्रेटिक प्रोसेस हो सकता है, लेकिन इस समय पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं हो रहा है। मालूम हो कि चुनाव आयोग के अधिकारी बीते 7 जनवरी को शांतिनिकेतन में सेन के घर प्रतीची गए थे और उनके एन्यूमरेशन फ़ॉर्म एंट्री में ''लॉजिकल गड़बड़ी'' को लेकर उन्हें एसआईआर हियरिंग नोटिस दिया था। चुनाव आयोग के मुताबिक, नोटिस इसलिए जारी किया गया क्योंकि सेन और उनकी मां अमिता सेन के बीच उम्र का अंतर, जैसा कि उनके एन्यूमरेशन फॉर्म पर डेटा एंट्री से कैलकुलेट किया गया था, 15 साल से कम था। हालांकि, 2002 के इलेक्टोरल रोल में उम्र का अंतर 19 साल बताया गया है। सेन ने इलेक्टोरल रोल (मतदाता सूची) रिवीजन के लोकतांत्रिक मूल्य और उन हालातों पर बात की जिनके तहत वे वोट देने के अधिकार को मजबूत कर सकते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इस तरह की प्रक्रिया सावधानी और सही समय के साथ की जानी चाहिए। उनके हिसाब से बंगाल के मामले में ये हालात ''मिसिंग'' हैं।सेन ने कहा-एसआईआर जल्दबाजी में किया जा रहा है, जिसमें मताधिकार वाले लोगों को आने वाले विधानसभा चुनाव में वोट देने के अपने हक को साबित करने के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करने का पूरा मौका देने के लिए काफी समय नहीं दिया जा रहा है। यह वोटर्स के साथ और इंडियन डेमोक्रेसी के साथ भी गलत है।एसआईआर के दौरान अपने अनुभव से बताते हुए, सेन ने कहा कि पोल अधिकारियों पर भी समय का दबाव साफ दिख रहा था। कभी-कभी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के पास ही काफी समय नहीं होता। सेन ने कहा-जब उन्होंने शांतिनिकेतन में मेरे होम सीट से वोट देने के मेरे अधिकार पर सवाल उठाया-जहां से मैंने पहले वोट दिया है, और जहां मेरा नाम, पता और दूसरी डिटेल्स ऑफिशियल रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड हैं-तो उन्होंने मुझसे मेरी जन्म की तारीख पर मेरी गुज़र चुकी मां की उम्र के बारे में पूछा, जबकि मैं खुद एक वोटर हूं, मेरी मां की डिटेल्स भी, मेरी तरह, उनके अपने ऑफिशियल रिकॉर्ड में स्टोर थीं। नोबेल विजेता अर्थशास्त्री ने आगे उन डॉक्यूमेंटेशन की मुश्किलों के बारे में बताया जिनका उन्हें सामना करना पड़ा, और कहा कि ये मुश्किलें गांव के इलाकों में पैदा हुए कई भारतीयों के लिए आम हैं। सेन ने कहा-गांव के भारत में पैदा हुए कई भारतीय नागरिकों की तरह (मैं उस समय के गांव शांतिनिकेतन में पैदा हुआ था), मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, और वोट देने की मेरी योग्यता के लिए मेरी तरफ से और पेपरवर्क पेश करने की ज़रूरत है। हालांकि यह मामला आखिरकार उनके लिए सुलझ गया, सेन ने उन नागरिकों के लिए चिंता जताई जिनके पास इसी तरह की मदद नहीं है।सेन ने कहा-भले ही मैं खुशी-खुशी (बीटल्स की तरह) कह सकता था-ओह, मैं अपने दोस्तों की थोड़ी मदद से काम चला लेता हूं। मुझे दूसरों की चिंता थी। उन्होंने कहा-मेरे इतने वफ़ादार दोस्त नहीं हैं। मेरे दोस्तों ने मुझे मज़बूत चुनाव आयोग के सख़्त दरवाज़ों से निकलने में मदद की।जब पूछा गया कि क्या एसआईआर पश्चिम बंगाल में किसी भी राजनीतिक पार्टी को राजनीतिक रूप से फ़ायदा पहुंचा सकता है, तो सेन ने कहा कि वह कोई पक्का अंदाज़ा नहीं दे सकते, और इस बात पर ज़ोर दिया कि लोकतांत्रिक ईमानदारी सबसे ऊपर रहनी चाहिए। सेन ने कहा-मैं कोई इलेक्शन एक्सपर्ट नहीं हूं, इसलिए मैं इस सवाल का जवाब पक्के तौर पर नहीं दे सकता। मुझे उन लोगों ने बताया है जो ज़्यादा जानते हैं, कि बीजेपी को कम अकाउंटिंग से फ़ायदा होगा। मुझे नहीं पता कि यह सच है या नहीं, लेकिन असली बात यह है कि चुनाव आयोग को एक गलत इंतज़ाम पर ज़ोर नहीं देना चाहिए और हमारे गर्व करने वाले डेमोक्रेसी को बेवजह गलती करने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए, चाहे फ़ायदा किसी को भी हो।समाज के उन हिस्सों के बारे में जिन्हें के दौरान बाहर किए जाने का सबसे ज़्यादा खतरा है, सेन ने गरीब नागरिकों को होने वाले स्ट्रक्चरल नुकसान की ओर इशारा किया। ''एक साफ़ जवाब होना चाहिए कि ज़रूरतमंद और गरीब लोग। नई वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अक्सर समाज के कमज़ोर लोगों के लिए पाना मुश्किल होता है। सेन ने कहा-नई वोटर लिस्ट में शामिल होने के लिए खास डॉक्यूमेंट्स पाने और दिखाने की ज़रूरी ज़रूरत में जो क्लास का भेदभाव दिख सकता है, वह गरीब लोगों के खिलाफ़ काम करेगा।बता दें कि 16 जनवरी को, जब चुनाव आयोग के अधिकारी सेन की एसआईआर हियरिंग के लिए पहुंचे, तो नोबेल पुरस्कार विजेता के एक पारिवारिक मित्र गीतिकांथा मजूमदार ने उनसे पूछा था-क्या भारत रत्न साइटेशन एक एसआईआर डॉक्यूमेंट के तौर पर काम करेगा? मजूमदार ने बाद में बताया था-मैं सवाल पूछकर मज़ाक कर रहा था। मैं चुनाव आयोग को यह मैसेज देना चाहता था कि वह एक ऐसे व्यक्ति को परेशान कर रहा है जिसे देश का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न मिला है।

बढ़ती अविवाहित प्रवृत्ति और मानसिक स्वास्थ्य : एक गंभीर विमर्श

अविवाहितों में मानसिक समस्याएं बढ़ रही हों तो करें शादी

डॉ. मनोज कुमार तिवारी
वरिष्ठ परामर्शदाता

शादी का बंधन केवल दो लोगों का मिलन नहीं, बल्कि एक संवेगात्मक सम्बल का साधन है। कुछ लोग जीवन भर अविवाहित रहकर किसी विशेष कार्य के लिए स्वयं को समर्पित कर देते हैं। अविवाहित लोग अपने जीवन में अकेलापन महसूस करते हैं, जो मानसिक समस्याएं पैदा करने लगता है। शादीशुदा जीवन में परिवार व बच्चों का साथ भी व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद करता है। अविवाहित लोगों में अकेलापन, सामाजिक दबाव व रिश्ते बनाने में कठिनाई जैसी मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं आती हैं। शोधों के अनुसार शादीशुदा लोगों में तनाव व अवसाद का स्तर अविवाहित लोगों की अपेक्षा कम होता है। अविवाहित लोगों में मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का जोखिम अधिक होता है। जीवन में अकेली महिलाओं पर शोध दर्शाते हैं कि महिलाएं स्वास्थ्य समस्याओं, गंभीर चोट, दुर्घटना तथा समायोजन संबंधी कठिनाइयों से जूझती है। उन्हें आर्थिक रूप से प्रतिकूल स्थिति का भी सामना करना पड़ता है। अधिकांश अविवाहित महिलाऐं यौन उत्पीड़न के भय से ग्रस्त रहती हैं जिससे उन्हें कई मनोवैज्ञानिक बीमारी, निराशा, दुश्चिंता, उदासी, अवसाद विकार व अलगाव की भावना जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी की एक स्टडी के अनुसार विवाहित लोगों की तुलना में सिंगल लोगों में दिल की बीमारियों का खतरा 5 फीसद ज्यादा होता है। विश्व में लगभग 47.35 मिलियन पुरुष तथा लगभग 41.81 मिलियन महिलाएं अविवाहित हैं। पिछले दो दशकों में अविवाहित व्यक्तियों की संख्या लगभग 21 फीसद से बढ़कर लगभग 35 फीसद हो गई है। एक सर्वे के अनुसार लगभग 23 फीसद युवा शादी नहीं करना चाहते हैं। 2019 में पुरुषों की लगभग 26.1 फीसद तथा महिलाओं की लगभग 19.9 फीसद आबादी शादी नहीं करना चाहती थी। एक तरह से देश के एक चौथाई से ज्यादा युवा लड़के-लड़कियां शादी नहीं करना चाहते। सरकार की एक रिपोर्ट (2019) के अनुसार शादी न करने वाले युवाओं की सबसे अधिक संख्या जम्मू और कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में दर्ज की गई है। अविवाहित व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति अलग पाई गई है जहां कुछ को अकेलापन व अवसाद का खतरा होता है, वहीं कुछ मजबूत सामाजिक नेटवर्क, स्वतंत्रता व व्यक्तिगत विकास से बेहतर महसूस करते हैं। एक बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह लेख गृहस्थ जीवन में रहने वालों को ध्यान में रखकर लिखा गया है। बैराग्य धारण करने वाले साधू संतो के लिए अविवाहित जीवन परम आनंद दायक व उत्तम मानसिक स्वास्थ्य का साधन होता है क्योंकि उनकी जीवनशैली, दिनचर्या, सोच विचार, अपेक्षाऐं, इच्छाऐं सामान्य व्यक्ति से अलग होती हैं। अविवाहित रहने की प्रवृत्ति में वृद्धि के कारण आर्थिक स्वतंत्रता उच्च शिक्षा कैरियर पर अधिक ध्यान जीवनशैली में बदलाव शादी के बाद की जिम्मेदारियों से बचने की इच्छा समाज में बढती स्वीकृत लिव इन रिलेशन का बढता प्रचलन एकांकी परिवार सामाजीकरण में दोष आत्मनिर्भरता के बढते अवसर स्वेच्छाचारिता की बढती सोच आधुनिक व सबल होने का दिखावा मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं

अकेलापन : जीवनभर अकेले रहने से अकेलापन महसूस होता है, खासकर जब आसपास के लोग शादीशुदा हों। परिवार का एकांकी होना। अस्वस्थ होने पर देखभाल हेतु लोगों के उपलब्ध न होने पर अविवाहित की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है।

सामाजिक दबाव : समाज द्वारा अविवाहित होने पर दबाव देना आम बात है क्योंकि अविवाहित रहना सामाजिक मानक के खिलाफ है जिससे सामाजिक दबाव होता है कि शादी कर लें। जिससे व्यक्ति खुद को अलग-थलग समझने लगता है।

रिश्तों की चिंता : एक समय के बाद खास कर माता पिता के मृत्यु हो जाने पर कोई साथी न मिलने या गलत साथी मिलने की चिंता सताने लगती है। उम्र ढलने के साथ मित्र व रिश्तेदारों से भी सम्पर्क कम होने लगता है जिससे चिंता और बढ जाती है।

आत्म-सम्मान में कमी : अकेलापन व सामाजिक दबाव के कारण अविवाहित लोगों के आत्म-सम्मान में कमी आने लगता है जिससे नकारात्मकता बढने लगती है।

अवसाद : लगातार अकेलापन व निराशा की भावना से अवसाद होता है। व्यक्ति अपने रुचिकर कामों में भी अरुचि रखने लगता है। उसके जीवन में उम्मीद कम तथा निराशा बढती है। समय रहते इसका प्रबंध न किया जाए तो व्यक्ति में आत्महत्या के विचार आने लगते हैं तथा आत्महत्या का प्रयास भी व्यक्ति कर सकता है।

बचाव सामाजिक नेटवर्क बनाएं : दोस्तों, परिवार और समान विचारधारा वाले लोगों के साथ मजबूत संबंध बनाएं। लोगों का सहयोग करें ताकि लोग आप की भी सहायता करें। शौक को पूरा करें : अपने अच्छे शौक की पहचान कर उसे पूरा करें तथा कोई गलत शौक हो तो उसे दूर करने का प्रयास करें। शौक के माध्यम से कौशल विकास करने का प्रयास करें।

व्यक्तिगत विकास : यात्रा करें, डायरी लिखें, संगीत सुने। ऐसे काम करें जो आपको खुशी दें और व्यक्तिगत विकास में मदद करें। अच्छे गुणों की पहचान कर उसे और विकसित करें।

स्वयं- देखभाल : स्वस्थ आहार, पर्याप्त पानी पीऐं, व्यायाम करें और पर्याप्त नींद लें। कैफीन और शराब का सेवन सीमित करें। नियमित दिनचर्या अपनाऐं, हो सके तो सहायक रखें।

सकारात्मक दृष्टिकोण रखने : विवाहित होने के बजाय अविवाहित होने के फायदों पर ध्यान दें। सकारात्मक सोचें, भविष्य के लिए अच्छी योजनाएं बनाऐं। आवश्यकता होने पर सहयोग लेने में संकोच न करें।

दुविधा में न रहें, ले स्पष्ट निर्णय : ऐसा पाया गया है कि जो लोग अविवाहित रहने की कमजोर इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ते हैं उनमें असमंजस और अनिर्णय की स्थिति बनी रहती है जिससे उनमें असुरक्षा की भावना बढ़ती है इसलिए यदि एक बार अविवाहित रहने का निर्णय तो उस पर दृढ़ रहें।

पेशेवर मदद लें : यदि अकेलापन या अवसाद हो तो मनोचिकित्सक, मनोवैज्ञानिक या काउंसलर से बात करें। वे भावनाओं को समझने और नकारात्मकता से निपटने में मदद करते हैं। विभिन्न एक्सरसाइज से तनाव कम करने में सहयोग दें सकते हैं।

समूह से जुड़ें : अविवाहित लोगों व समान अनुभवों वाले लोगों के समूहों में शामिल होना अच्छे मानसिक स्वास्थ्य में सहायक होता है। अपनी भावनाओं को साझा करने व समझने में आसानी होती है।

शादी का लें निर्णय : अविवाहित यदि अकेले रहने से लंबे समय तक व गंभीर मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं का सामना कर रहें हो तो उन्हें एक बार शादी कर लेने का गंभीरता से विचार करके निर्णय लेना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना अविवाहित लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है इसके लिए अपने सामाजिक नेटवर्क को मजबूत करना, दोस्तों और परिवार से जुड़ाव, शौक को पूरा करना महत्वपूर्ण है। अकेलेपन को दूर करने के लिए व्यक्ति को अपनी रुचियों व सामाजिक गतिविधियों में संलग्न रहना अच्छा होता है। नियमित योग, ध्यान और व्यायाम करने से भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। अपने आप हमेशा अच्छे व रुचिकर कार्यों में व्यस्त रखना मानसिक स्वास्थ्य के लिए उत्तम है।

ममता बनर्जी की पुरानी फोटो शेयर कर बीजेपी ने किया हमला

आनंदपुर वेयरहाउस अग्निकांड

निज संवाददाता : भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने आनंदपुर वेयरहाउस में लगी आग को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की प्रमुख ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। अमित मालवीय ने कहा कि गुरुवार 29 जनवरी को आनंदपुर वेयरहाउस में लगी आग में मरने वालों की संख्या बढ़कर 27 हो गई। इसमें और लोगों के मारे जाने की आशंका है। लेकिन बंगाल की मुख्यमंत्री अभी तक पीड़ित परिवारों से मिलने और उन्हें सहानुभूति जताने तक नहीं गईं। अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा-27 लोग मारे गए हैं और कई और लोगों के मारे जाने की आशंका है। परिवार दुख में हैं। पीड़ित जवाब का इंतजार कर रहे हैं। फिर भी, ममता बनर्जी अभी तक पीड़ितों से मिलने नहीं गई हैं। अमित मालवीय ने वाओ मोमो के सीईओ के साथ ममता बनर्जी की एक पुरानी फोटो शेयर की। ₹

मालवीय ने कहा-लेकिन जब ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में आई-पैक के फाउंडर के घर पर छापा मारा, तो मुख्यमंत्री तुरंत उनके घर पहुंच गईं। प्राथमिकताएं शब्दों से ज्यादा बोलती हैं। उसी मुख्यमंत्री को 2023 में मैड्रिड में वाओ मोमो के सीईओ सागर दरयानी के साथ पोज़ देने में कोई झिझक नहीं हुई, जबकि आज, इस त्रासदी से जुड़े अवैध ऑपरेशन्स और रेगुलेटरी नाकामियों पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पीड़ितों के लिए सहानुभूति गायब है। जल्दबाज़ी सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जो राजनीतिक रूप से करीब हैं। बंगाल देख रहा है। गौरतलब है कि कोलकाता पुलिस ने बीते शुक्रवार को बताया था कि फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस में लगी भीषण आग की जांच कर रही टीम ने वाओ मोमो के मैनेजर और डिप्टी मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी गुरुवार देर रात हुई और दोनों लोगों की पहचान मोमोरंजन सिट और राजा चक्रवर्ती के रूप में हुई है। मोमोरंजन फैक्ट्री-कम-वेयरहाउस का मैनेजर है, जबकि राजा चक्रवर्ती उस आउटलेट का डिप्टी मैनेजर है। मालूम हो कि कोलकाता के आनंदपुर में बीते 26 जनवरी को आग लग गई। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के जानकार सूत्रों के अनुसार, कई लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं, जिससे दिन में मरने वालों की संख्या और बढ़ने की आशंका है।

26 जनवरी की सुबह आनंदपुर में एक गोदाम के अंदर आग लगी थी। उस समय अंदर सो रहे कई मजदूर चपेट में आए थे। राज्य अग्निशमन सेवा विभाग और फोरेंसिक टीम की प्रारंभिक रिपोर्ट में कहा गया कि आग वाओ मोमो फैक्ट्री से नहीं, बल्कि पास के दुर्भाग्यपूर्ण पुष्पांजलि डेकोरेटर के गोदाम से लगी थी। हालांकि घटना के बाद गिरफ्तार किए गए पुष्पांजलि गोदाम के मालिक गंगाधर दास ने दावा किया कि आग सबसे पहले मोमो फैक्ट्री से फैली थी।

कोलकाता नगर निगम के आर्काइव्ज़ में भारत के आज़ादी के बाद के इतिहास को सार्वजनिक करने की मांग

निज संवाददाता : कोलकाता नगर निगम (केएमसी) के आर्काइव्ज़ में भारत के आज़ादी से पहले के इतिहास के एक अहम दौर के रिकॉर्ड हैं, और वे आम लोगों के लिए उपलब्ध होने चाहिए। यह प्रस्ताव तृणमूल के एक पार्षद ने गुरुवार को कोलकाता नगर निगम की मासिक बैठक में रखा। वार्ड 98 के पार्षद अरूप चक्रवर्ती ने कहा कि ऐसा कदम ऐसे समय में ज़रूरी है जब इतिहास और सच्चाई को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिश हो रही है। चक्रवर्ती ने कहा कि नगर निगम अधिकारियों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जिससे लोग टाउन हॉल जाकर आर्काइवल रिकॉर्ड देख सकें, जहां एक म्यूज़ियम और रिसोर्स सेंटर बनाया जाएगा। टाउन हॉल में ही 12,000 से ज़्यादा किताबें और डॉक्यूमेंट्स हैं, जिनके डिजिटाइज़ होने की भी उम्मीद है। उन्होंने सभी पार्षदों की महीने की मीटिंग में कहा-जब हम इतिहास को तोड़-मरोड़कर पेश करने की कोशिशें देख रहे हैं, तो केएमसी आर्काइव्ज़ में उपलब्ध रिकॉर्ड को डिजिटाइज़ करना और भी ज़रूरी हो जाता है। कई जानकार और पत्रकार ऐतिहासिक रिकॉर्ड देखना चाहेंगे। अपने भाषण में, चक्रवर्ती ने बीजेपी पर निशाना साधा, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि बीजेपी ने सच को तोड़-मरोड़कर बंगाल के आइकॉन को ''गलत तरीके से पेश किया और बेइज़्ज़त किया। उन्होंने कहा-किसी ने कहा कि राजा राममोहन राय अंग्रेजों के एजेंट थे। फिर किसी और ने कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने नोबेल शांति पुरस्कार जीता था। मालूम हो कि मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कथित रूप से नवंबर में कहा था- राजा राम मोहन राय भी अंग्रेजों के दलाल के रूप में देश में काम करते रहे। हालांकि, बाद में परमार ने ''माफी और पछतावे'' का एक बयान जारी किया। जाहिर तौर पर बंगाल बीजेपी के अनुरोध और नेशनल लीडरशिप के निर्देशों के बाद उन्होंने ऐसा कहा। बंगाल के अपने पहले दौरे पर, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बुधवार को दुर्गापुर में पार्टी वर्कर्स को संबोधित करते हुए कहा कि रवींद्रनाथ टैगोर ने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। टैगोर 1913 में लिटरेचर का प्राइज़ जीतने वाले पहले एशियन थे। केएमसी डिबेट के दौरान बोलते हुए, वार्ड 23 के बीजेपी पार्षद विजय ओझा ने प्रपोज़ल का स्वागत किया, लेकिन कहा कि उन्हें पक्का नहीं पता कि यह ''साफ़ दिल'' से प्रपोज़ किया गया था या इसमें ''नफ़रत'' का एलिमेंट था। उन्होंने कहा-अगर प्रपोज़ल के पीछे नफ़रत है, तो यह अच्छा नहीं है। जब कुछ तृणमूल पार्षदों ने ओझा के भाषण में रुकावट डालने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा-मुझे बोलने दो। मैं एक ओझा हूं, फिर भी मैं बांग्ला में बोल रहा हूं। क्या आपको यह पसंद नहीं है? ओझा ने कहा-मेरे पिता कोलकाता में पैदा हुए थे। मैं इसी शहर में पैदा हुआ हूं। केएमसी चेयरपर्सन माला रॉय ने ओझा के समर्थन में दखल दिया और तृणमूल पार्षदों से उन्हें बोलने देने को कहा। केएमसी के सूत्रों ने बताया कि सिविक बॉडी के आर्काइव्ज़ में अप्रैल 1924 में मेयर बनने के बाद सीआर दास के पहले भाषण और अगस्त 1930 में मेयर बनने पर सुभाष चंद्र बोस के भाषण शामिल हैं। 1924 में, स्थानीय सरकारों का इंडियनाइज़ेशन शुरू होने के बाद सीआर दास उस समय के कलकत्ता कॉर्पोरेशन के मेयर बने। आर्काइव्ज़ में 1943 के बंगाल अकाल और 1946 के दंगों के दौरान शहर की डिटेल्ड जानकारी है। कई ऐसी तस्वीरें भी हैं जो बहुत कम देखी जाती हैं। केएमसी के एक अधिकारी ने कहा-जब दास मेयर बने, तो उन्होंने सुभाष बोस को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पद पर अपॉइंट किया। बदकिस्मती से, बोस को कुछ ही महीनों में हिरासत में ले लिया गया। डिप्टी मेयर, हुसैन शहीद सुहरावर्दी ने सुभाष बोस की गिरफ्तारी के बारे में काउंसिल मीटिंग में बात की थी। वह भाषण आर्काइव्ज़ में है। सुहरावर्दी, जो उस समय एक होनहार युवा मुस्लिम पॉलिटिशियन थे, बाद में बंगाल के प्राइम मिनिस्टर बने और आज़ादी के बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने।

अजब-गजब

दुनिया का 'सबसे शापित गांव' : यांग्सी

जहां आधी से ज्यादा आबादी की लंबाई केवल 2 से 3 फीट के बीच

निज संवाददाता : चीन के शिचुआन प्रांत का एक छोटा और सुदूर गांव यांग्सी भी शामिल है, जिसे पूरी दुनिया आज 'सबसे शापित गांव' या 'बौनों का गांव' के नाम से जानती है। यह गांव अपने अनोखे भूगोल या संस्कृति के लिए नहीं, बल्कि यहां रहने वाले लोगों के असामान्य शारीरिक विकास के कारण चर्चा में है। यांग्सी गांव की सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यहां की आधी से ज्यादा आबादी की लंबाई केवल 2 से 3 फीट के बीच है।

स्थानीय रिपोर्टों के मुताबिक, यह रहस्यमय स्थिति साल 1951 के बाद से देखने को मिल रही है। गांव में जन्म लेने वाले बच्चे सामान्य और स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन जैसे ही वे 5 से 7 वर्ष की उम्र तक पहुंचते हैं, उनकी लंबाई का बढ़ना अचानक रुक जाता है। इसके बाद जीवनभर उनका कद लगभग वही रह जाता है। बीते छह दशकों से यह सिलसिला बिना किसी स्पष्ट कारण के जारी है। इस अजीब घटना ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को भी उलझन में डाल दिया है। हाल ही में एक डॉक्यूमेंट्री के दौरान विशेषज्ञों की टीम ने गांव की मिट्टी, पीने के पानी, हवा और यहां उगने वाले अनाज तक की गहन जांच की। आधुनिक तकनीकों और लैब टेस्ट के बावजूद ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक या चिकित्सकीय कारण सामने नहीं आया, जो इस सामूहिक बौनेपन को पूरी तरह समझा सके। विशेषज्ञ इसे 'स्टंटेड ग्रोथ' यानी अवरुद्ध शारीरिक वृद्धि का मामला तो मानते हैं, लेकिन सवाल यह है कि यह समस्या सिर्फ इसी गांव तक सीमित क्यों है। ग्रामीणों के बीच इस रहस्य को लेकर अलग-अलग मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ बुजुर्ग इसे पीढ़ियों पुराना श्राप मानते हैं। लोक कथाओं के अनुसार, पूर्वजों को गलत समय या गलत नक्षत्र में दफनाने, या किसी दैवीय शक्ति के क्रोध के चलते गांव पर यह विपत्ति आई।

वहीं कुछ इतिहासकारों का मानना है कि यह प्रभाव द्वितीय विश्व युद्ध के समय जापान द्वारा किए गए रासायनिक प्रयोगों या जहरीली गैस के कारण हो सकता है, जिसका असर लोगों के डीएनए पर पड़ा। बताया जाता है कि 1950 के दशक में इस क्षेत्र में एक रहस्यमयी बीमारी फैली थी, जिसके बाद से नई पीढ़ी के बच्चों की शारीरिक बढ़त रुकने लगी। हाल के वर्षों में वैज्ञानिकों ने जेनेटिक म्यूटेशन की दिशा में भी जांच शुरू की है, लेकिन अब तक 60 साल पुराने इस रहस्य की परतें पूरी तरह नहीं खुल सकी हैं।

18 दिनों तक खिचड़ी और अचार खाकर क्रू ने पूरी की समुद्री यात्रा

बिना किसी तकनीक या बिजली के जहाज पहुंचा ओमान

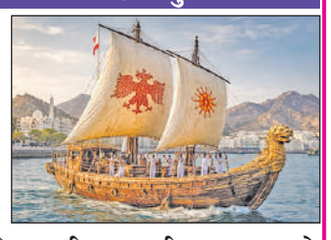

निज संवाददाता : भारत की प्राचीन समुद्री विरासत को जीवंत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज कराते हुए भारतीय नौसेना का पारंपरिक पाल विधि से निर्मित जहाज आईएनएसवी 'कौंडिन्य' 18 दिनों की कठिन समुद्री यात्रा पूरी कर गुजरात से ओमान पहुंचा है। यह जहाज 29 दिसंबर को गुजरात के पोरबंदर से रवाना हुआ था और 14 जनवरी को ओमान की राजधानी मस्कट पहुंचने की खबर आ गई है। इस विशेष यात्रा का उद्देश्य भारत के प्राचीन जहाज निर्माण कौशल और समुद्री परंपराओं को पुनर्जीवित करना है। आईएनएसवी 'कौंडिन्य' को 5वीं शताब्दी के भारतीय जहाजों के मॉडल पर तैयार किया गया है। इसकी सबसे खास बात यह है, इसे बिना किसी कील या धातु के इस्तेमाल के बनाया गया है। लकड़ी के तख्तों को नारियल के रेशों से रस्सियों द्वारा सिलकर जोड़ा गया है, जिसे प्राचीन 'टांका पद्धति' कहा जाता है। खास बात यह है कि इस जहाज में न तो इंजन है, न बिजली, न जीपीएस और न ही कोई आधुनिक नेविगेशन सिस्टम। यह पूरी तरह हवा के रुख के सहारे कपड़े के पाल (सढ़) से चलता है। जहाज पर कोई केबिन या कमरा नहीं है। क्रू मेंबर्स खुले डेक पर स्लीपिंग बैग में सोते थे। रात के समय अन्य जहाजों को संकेत देने के लिए उनके पास केवल हेडलैंप थे। पीने का पानी मटकों में रखा गया था और 18 दिनों तक क्रू ने खिचड़ी और अचार खाकर यात्रा पूरी की। इस जहाज के मस्कट पहुंचने की जानकारी प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए साझा की। जिसके बाद से इसकी चर्चा चारों ओर हो रही है। यहां बताते चलें कि जहाज का नाम पहली सदी के प्रसिद्ध भारतीय नाविक कौंडिन्य के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने हिंद महासागर पार कर मेकांग डेल्टा तक यात्रा की थी और वहां एक कंबोडियाई राजकुमारी से विवाह किया था। इस जहाज का डिजाइन अजंता गुफाओं की 5वीं सदी की एक पेंटिंग पर आधारित है। भारत सरकार ने वर्ष 2023 में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी। इसके तहत संस्कृति मंत्रालय, भारतीय नौसेना और गोवा की निजी कंपनी होड़ी इनोवेशंस के बीच त्रिपक्षीय समझौता हुआ। जहाज को फरवरी 2025 में गोवा में लॉन्च किया गया था। आईएनएसवी कौंडिन्य के पालों पर गंडभेरुंड और सूर्य के प्रतीक अंकित हैं, आगे की ओर सिंह याली की आकृति और डेक पर हड़प्पा शैली का प्रतीकात्मक पत्थर का लंगर लगाया गया है। यह जहाज भारत की प्राचीन समुद्री शक्ति, व्यापार और सांस्कृतिक आदान-प्रदान की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक बनकर उभरा है।

धर्म

हिंदू धर्म में है विशेष महत्व

1 फरवरी : माघ पूर्णिमा

निज संवाददाता : माघ मास की पूर्णिमा का हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। इस साल में माघ पूर्णिमा 1 फरवरी यानी रविवार को मनाई जाएगी। पंचांग के अनुसार, पूर्णिमा तिथि 1 फरवरी 2026 को सुबह 5:52 बजे से शुरू होकर 2 फरवरी 2026 को रात 3:38 बजे तक रहेगी। इस दौरान विशेष पूजा, स्नान और दान करने का विधान बताया गया है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन की गई साधना और धार्मिक अनुष्ठान से जीवन में पापों का नाश होता है और आध्यात्मिक उन्नति की प्राप्ति होती है। शास्त्रों के अनुसार, माघ पूर्णिमा को स्नान और पूजा करने से व्यक्ति के पाप नष्ट होते हैं और उसे धर्म की प्राप्ति होती है। इस दिन की गई साधना व्यक्ति को विशेष रूप से मानसिक और आत्मिक शुद्धि प्रदान करती है। मान्यता है कि माघ मास की पूर्णिमा में स्नान करने से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। भगवद पुराण और पद्म पुराण में उल्लेख मिलता है कि माघ पूर्णिमा में गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत पुण्यदायी होता है। इस दिन किए गए दान और तप से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। माघ पूर्णिमा पर घर में या नदी किनारे पूजा और हवन करना शुभ माना गया है। शास्त्रों में बताया गया है कि इस दिन दीपक जलाना, आरती करना और भगवान विष्णु या शिव की पूजा करना अत्यंत फलदायी है। पुराणों में कहा गया है कि माघ पूर्णिमा में दान करने से दस वर्षों तक किए गए पाप भी नष्ट हो जाते हैं। धार्मिक अनुष्ठानों में फल, दूध, मिठाई और वस्त्र दान करना विशेष महत्व रखता है। यह दिन साधकों के लिए अपने कर्मों की शुद्धि और मन की शांति प्राप्त करने का अवसर है। माघ पूर्णिमा को पवित्र नदियों में स्नान करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार, गंगा, यमुना या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करने से शरीर, मन और आत्मा की अशुद्धियां दूर होती हैं। साथ ही, इस दिन किए गए दान का फल कई गुना बढ़ जाता है। गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन और भोजन दान करने से जीवन में सुख-समृद्धि आती है। स्नान और दान के साथ ही मन से भगवान की भक्ति करना आवश्यक है। यह संयोजन जीवन में धार्मिक और आध्यात्मिक लाभ प्रदान करता है। माघ पूर्णिमा का व्रत और पूजा करने से जीवन में रोग, भय और दुखों का नाश होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन की गई साधना से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। माघ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान और दान करने से पूर्व जन्मों के पाप भी समाप्त हो जाते हैं। भक्तों का मानना है कि इस दिन किए गए धार्मिक अनुष्ठान और व्रत से मन की इच्छाएं पूरी होती हैं और जीवन में स्थायी सुख और शांति आती है। यही कारण है कि माघ पूर्णिमा को अत्यंत पुण्यदायी तिथि माना गया है।

30 साल बाद बन रहा है शनि का विशेष योग

निज संवाददाता : शनिदेव को कर्मफलदाता और न्याय देने वाला देवता कहा जाता है। उनको नौ ग्रहों का स्वामी माना जाता है। शनि ग्रह के अस्त होने से आम लोगों के जीवन में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। शनि ग्रह अनुशासन, धर्मबुद्धि, कर्म और आध्यात्मिकता पर गहरा प्रभाव डालता है। दरअसल, ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है कि ग्रह एक तय समय के बाद अपनी-अपनी राशि बदलते रहते हैं। हर ग्रह का एक निश्चित अंतराल के बाद राशि बदलना सामान्य बात है। ग्रहों की चाल का संबंधित राशियों पर अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है। इस समय शनि ग्रह मीन राशि में गोचर कर रहे हैं।ज्योतिष शास्त्र के मुताबिक, शनि देव इस साल 13 मार्च की शाम 7 बजकर 13 मिनट पर मीन राशि में अस्त हो जाएंगे। इस तरह का योग लगभग 30 साल बाद बन रहा है। इसका प्रभाव खासकर तीन राशियों पर ज्यादा पड़ेगा और ये प्रभाव सकारात्मक रहनेवाला है। शनि ग्रह पॉजिटिव एनर्जी और सौभाग्य लेकर आएगा। आइए अब जानते हैं कि शनि के अस्त होन से किन-किन राशियों को लाभ होगा।धनु राशिमीन राशि में शनि के अस्त होने से धनु राशि वालों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा। सरकारी नौकरीपेशा लोगों को मनचाही पदोन्नति मिलने की संभावना है। उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए अतिरिक्त जिम्मेदारियां मिलेंगी। नया व्यवसाय शुरू करने वालों के लिए यह अच्छा समय है। आपकी आय में वृद्धि होगी, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। छात्रों को पढ़ाई में प्रगति मिलेगी। विदेश यात्रा की संभावना है। पति-पत्नी दोनों लंबी यात्रा पर साथ जा सकते हैं।कुंभ राशिशनि के अस्त होने से कुंभ राशि वालों के लिए शुभ फल देगा। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होगा। अचानक धन प्राप्ति होगी। इसके परिणामस्वरूप पुराने कर्ज चुकाने में सफलता मिलेगी। संपत्ति संबंधी मामलों में अनुकूल निर्णय प्राप्त होगा। लंबे समय से लंबित कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया जाएगा। कार्यक्षेत्र संबंधी समस्याओं का समाधान होगा। परिवार में आर्थिक संकट कम होगा। करियर में अपेक्षित लाभ होगा। नया व्यवसाय शुरू करने की संभावना है। अतीत में किए गए निवेश से अधिक लाभ प्राप्त होगा।मीन राशिमीन राशि में शनि के अस्त से आपके लिए धन और प्रसिद्धि लेकर आएगा। आपके परिवार की आर्थिक परेशानियां मार्च से दूर होने लगेंगी। आप पुराने कर्ज चुका देंगे। संपत्ति अच्छे दाम पर बिकेगी। कारोबारियों को तरक्की और मुनाफा मिलेगा। व्यापार में नए सौदे होंगे। आप घर, गहने या वाहन खरीद सकते हैं। अविवाहित लोगों को जल्द ही एक अच्छा रिश्ता मिलेगा।

रेगिस्तान में हीरों की खुदाई के दौरान मिला 500 साल पुराना खजाना

लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ था सोना-चांदी से भरा जहाज

निज संवाददाता : भारत आ रहा खजाने से लदा जहाज 5 सौ साल पहले नामीबिया के रेगिस्तान में दफन हो गया था, जो अब जाकर बरामद हुआ है। नामीबिया के रेगिस्तान में हीरों की खुदाई के दौरान मजदूरों को रेत के नीचे से अजीब-सी ठक-ठक की आवाज सुनाई देने लगी। शुरुआत में इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज किया गया, लेकिन जब खुदाई आगे बढ़ी तो धीरे-धीरे रेत के नीचे छिपा 500 साल पुराना एक ऐसा खजाना सामने आया, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। यह खोज नामीबिया के ओरान्जेमुंड इलाके में हुई, जहां हीरा खनन कंपनी नामदेब की ओर से खुदाई का काम चल रहा था।

मजदूर जब गहराई में पहुंचे तो उन्हें लकड़ी के अजीब ढांचे जैसे टुकड़े दिखाई दिए, जिनमें जगह-जगह तांबे के हिस्से भी जुड़े हुए थे। शुरुआती तौर पर कर्मचारियों को यह बेकार का मलबा लगा और कुछ टुकड़ों को किनारे कर दिया गया। लेकिन जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ी, वहां से हाथी दांत और चमकदार सिक्के मिलने लगे। तेज धूप में जब इन सिक्कों पर रोशनी पड़ी तो उनकी चमक ने सभी को हैरान कर दिया और तभी एहसास हुआ कि वे किसी साधारण चीज नहीं, बल्कि एक बड़े खजाने के करीब पहुंच चुके हैं। सूचना मिलते ही पुरातत्वविदों और विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की गई। पड़ताल में सामने आया कि यह अवशेष 16वीं सदी के एक पुर्तगाली जहाज के हैं, जिसका नाम 'बॉम जीसस' या 'गुड जीसस' बताया गया। यह जहाज वर्ष 1533 में पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से भारत के लिए रवाना हुआ था। इसका उद्देश्य भारत से मसाले और रेशम लाना और बदले में सोना-चांदी व अन्य कीमती सामान पहुंचाना था। हालांकि, रास्ते में यह जहाज अचानक लापता हो गया और लंबे समय तक खोज के बाद यह मान लिया गया था कि शायद किसी भयानक तूफान में यह समुद्र में डूब गया। विशेषज्ञों के अनुसार, यह जहाज समुद्र तट के पास दुर्घटनाग्रस्त हुआ और समय के साथ समुद्र पीछे हटता गया, जिससे जहाज रेत में दबता चला गया। सदियों तक रेगिस्तान की रेत ने इसे सुरक्षित रूप से ढक कर रखा। खुदाई में मिले खजाने में किंग जॉन तृतीय के शासनकाल के 2000 से अधिक शुद्ध सोने के सिक्के, 105 से ज्यादा कीमती हाथी दांत, करीब 17 टन तांबे की ईंटें, बड़ी संख्या में चांदी के सिक्के, मध्यकालीन तोपें, तलवारें और उस दौर के उन्नत नेविगेशन उपकरण शामिल हैं।

भारत में निपाह वायरस के फैलने का जोखिम कम

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दिया भरोसा

निज संवाददाता : विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने शुक्रवार को कहा कि भारत में निपाह वायरस के फैलने का जोखिम कम है और देश में वायरस संक्रमण के दो मामले सामने आने के बाद यात्रा या व्यापार प्रतिबंध लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह घटना कई एशियाई देशों द्वारा अपने क्षेत्रों में आने वाले लोगों में वायरस के लक्षणों की जांच तेज करने के बाद हुई है। चूंकि भारत पहले भी निपाह के प्रकोप को नियंत्रित करने की अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है, इसलिए विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने यह मान लिया है कि मानव-से-मानव संक्रमण में वृद्धि का कोई प्रमाण नहीं है।

डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अन्य भारतीय राज्यों या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसके फैलने की संभावना कम मानी जाती है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंगलवार को पुष्टि की कि पिछले साल दिसंबर से अब तक पश्चिम बंगाल में निपाह वायरस रोग के केवल दो मामले सामने आए हैं। इसके बाद, केंद्र ने पश्चिम बंगाल सरकार के समन्वय से प्रोटोकॉल के अनुसार त्वरित और व्यापक जन स्वास्थ्य उपाय शुरू किए। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने आगे कहा कि जोखिम मूल्यांकन, निगरानी और प्रकोप से निपटने के प्रयासों में सहयोग देने के लिए भारत में राष्ट्रीय और राज्य स्वास्थ्य अधिकारियों के साथ मिलकर काम करना जारी रखे हुए है। सरकार ने निगरानी, प्रयोगशाला परीक्षण, संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण उपायों और जमीनी स्तर पर जांच को बढ़ावा दिया है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि पुष्टि किए गए मामलों से जुड़े कुल 196 संपर्कों की पहचान की गई, उनका पता लगाया गया, उन पर नज़र रखी गई और उनकी जांच की गई। पता लगाए गए सभी संपर्कों में कोई लक्षण नहीं पाए गए और निपाह वायरस रोग के लिए उनकी जांच नकारात्मक आई है।

देहरादून की हरियाली पर मंडराया खतरे का साया

'विशेष' कीट की वजह से काटने पड़ सकते हैं 20 हजार पेड़

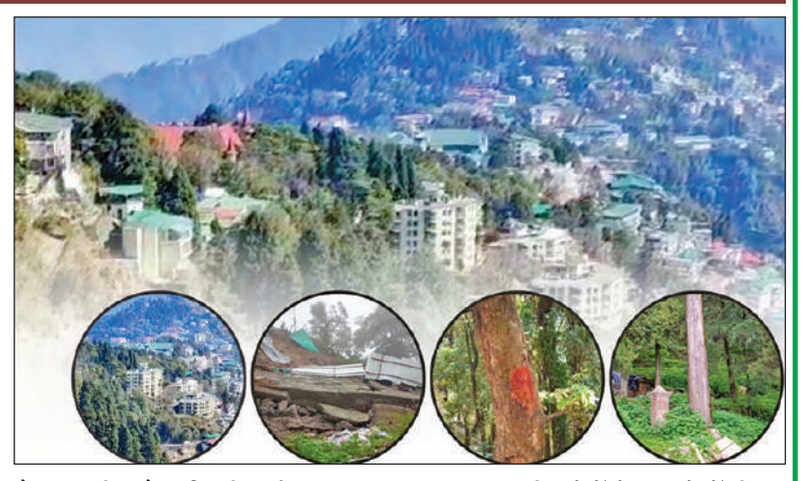

निज संवाददाता : उत्तराखंड के देहरादून जिले के साल के वनों पर होपलो कीट (साल बोरर कीट) के बढ़ते हमले से हरियाली खतरे में आ गई है। यह कीट साल के पेड़ों को भीतर से खोखला करता है, जिससे उनका जीवन गंभीर रूप से प्रभावित होता है। होपलो सबसे पहले पेड़ की छाल में छोटे छेद बनाकर अंडे देता है। अंडों से निकलने वाली लार्वा तने के अंदर सुरंग बनाकर हृदयकाष्ठ को खोखला करती है। इससे पेड़ का पानी और पोषक तत्वों का प्रवाह रुक जाता है, और समय के साथ पेड़ ऊपर से सूखकर कमजोर होकर गिरने लगता है। प्रभावित पेड़ों से तने में छेद, रस का रिसाव और बुरादा गिरना दिखाई देता है, जो संक्रमण के प्रमुख संकेत हैं।उत्तराखंड वन विभाग के अनुसार देहरादून वन प्रभाग में करीब 12 हजार, कालसी में 5000 और मसूरी में 3000 से अधिक साल के पेड़ होपलो से प्रभावित हैं। तीनों प्रभागों में साल के वनों की हिस्सेदारी करीब 70 फीसद है। गंभीर रूप से संक्रमित पेड़ों को कटान (कंटेनमेंट फेलिंग) के माध्यम से जंगल से बाहर निकालकर नष्ट किया जाता है, ताकि कीट का फैलाव रोका जा सके। कम प्रभावित पेड़ों में कीट आकर्षक ट्रैप, तने पर कीटनाशक पेस्टिंग और जंगल की सफाई जैसे उपाय किए जाते हैं। इतना ही नहीं वन विभाग ने समस्या के समाधान के लिए वन अनुसंधान संस्थान (एफआरआई) की टीम से मदद मांगी है। एफआरआई ने देहरादून वन प्रभाग का निरीक्षण कर लिया है, जबकि कालसी और मसूरी में टीम का दौरा प्रस्तावित है। वरिष्ठ विज्ञानी डॉ. अरुण प्रताप के अनुसार, होपलो का ठोस उपचार नहीं है, लेकिन संक्रमित पेड़ों की पहचान और उचित कार्रवाई संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करती है। सालाना कटान के अनुसार हर वर्ष लगभग 2000 पेड़ इस कीट के कारण काटने पड़ते हैं। इस वर्ष होपलो कीटों का प्रकोप सामान्य से अधिक होने की आशंका है, जिससे देहरादून के साल के वनों को गंभीर नुकसान का खतरा है। वन विभाग लगातार निरीक्षण, कीट नियंत्रण और जंगल की सफाई के माध्यम से इस समस्या से निपटने की कोशिश कर रहा है। इन खास ट्रैपों में कीट आकर्षित होकर फंसते हैं। इसके लिए साल के कुछ पेड़ों को काटकर कीटों के लिए चारा तैयार किया जाता है। कई जगह इससे 50 से 70 फीसद तक कीट पकड़ने में सफलता मिलती है। यह कम प्रभावित पेड़ों के मामले में किया जाता है। इसके अलावा तने पर कीटनाशक का छिड़काव/पेस्टिंग (वैज्ञानिक निर्देश अनुसार) किया जाता है। इसमें लार्वा और वयस्क कीट मर जाते हैं। इसके अलावा जंगल की सफाई और सूखी लकड़ी हटाने की कार्रवाई भी की जाती है। क्योंकि सूखे पत्ते, टूटे तने, मरी लकड़ी आदि कीट के प्रजनन स्थान बनते हैं। इनकी सफाई संक्रमण को रोकने में बहुत मदद करती है।वन विभाग के अधिकारियों के अनुसार इस वर्ष होपलो कीटों का प्रकोप कुछ अधिक है। क्योंकि, सामान्य रूप में साल के पेड़ों में यह कीट पाए ही जाते हैं। जिस कारण एक वन प्रभाग में औसतन दो हजार के करीब पेड़ों को इस कीट रोग के कारण काटना पड़ जाता है। इस वर्ष कुछ अधिक पेड़ इस कीट की भेंट चढ़ सकते हैं।

तबीयत खराब हुई तो 6 महीने की गर्भवती निकली 17 साल की लड़की

- 7 लड़कों ने किया था गैंगरैप

तमिलनाडु में अजीबो-गरीब मामला

निज संवाददाता : तमिलनाडु के तंजौर जिले के अय्यमपेट्टई इलाके की 17 साल की एक लड़की के साथ गैंगरेप करने के आरोप में पुलिस ने 7 लोगों को पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया है। इस घटना से इलाके में हड़कंप मच गया है। तंजौर जिले के अय्यमपेट्टई के पास एक गांव की रहने वाली लड़की की दोस्ती 2022 में उसी इलाके के अप्पू (उर्फ) एस. सुरेंद्रन पांडियन से हुई थी।

दावा किया जा रहा है कि दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई। इसके बाद सुरेंद्रन पांडियन ने लड़की के साथ गैंगरेप किया। हालांकि बाद में दोनों अलग हो गए। इसके बाद साल 2025 से लड़की पुन्नियानल्लर गांव के रहने वाले विनायकमुर्ती के 20 साल के बेटे मणिमारन के संपर्क में आई। साथ ही उसने पशुपति कोविल के रहने वाले कुमार के 24 साल के बेटे सुधन उर्फ जयसुधन से भी दोस्ती की। ऐसा कहा जाता है कि लड़की एक-दूसरे को जाने बिना एक-दूसरे के साथ रहती थी। इस बीच, पिछले कुछ दिनों से लड़की की तबीयत खराब चल रही थी, जिसके बाद लड़की के माता-पिता ने उसे इलाज के लिए कुंभकोणम सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि लड़की 6 महीने की गर्भवती है। इससे माता-पिता हैरान रह गए और जब उन्होंने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि मणिमारन और जयसुधन ने उसके साथ गैंगरेप किया है। इस संबंध में बाल संरक्षण समिति के अधिकारियों को सूचना मिली। तुरंत, उन्होंने लड़की को पापनासम महिला पुलिस स्टेशन ले जाकर शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस ने लड़की से पूछताछ की तो उसने बताया कि मणिमारन और जयसुधन ने उसके साथ गैंगरेप किया। इसके अलावा, उसने बताया कि सुरेंद्रन पांडियन, अय्यमपेट्टई के एम. विश्वनाथन, आर. रॉकी उर्फ राकेश, आर. आकाश, एम. षणमुगम, पुन्नियानल्लर के रहने वाले सरवनन के बेटे अशोक ने भी उसके साथ रेप किया।

इसके बाद, पापनासम महिला पुलिस निरीक्षक उषा ने पुलिस के साथ मणिमारन और जयसुधन से पूछताछ की। इसमें पता चला कि दोनों ने लड़की के साथ गैंगरेप किया था। इसके बाद पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मणिमारन और जयसुधन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा सुरेंद्रन पांडियन सहित 5 अन्य को कल पोक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया। पुलिस विश्वनाथन की तलाश कर रही है जो फरार है। इसके अलावा, पुलिस ने लड़की को मेडिकल जांच के लिए सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। इस घटना से अय्यमपेट्टई इलाके में हड़कंप मच गया।

नाम में गड़बड़ी को लेकर झूलन गोस्वामी को एसआईआर सुनवाई के लिए बुलाया गया

निज संवाददाता : भारत की पूर्व महिला क्रिकेट टीम की कप्तान झूलन गोस्वामी को उनके दो भाई-बहनों के साथ उनके पिता के नाम में गड़बड़ी को लेकर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (एसआईआर) प्रोसेस के तहत सुनवाई के लिए बुलाया गया है, एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि उनके पिता का नाम कुछ डॉक्यूमेंट्स में ''निशिथ रंजन गोस्वामी'' और कुछ में ''निशिथ गोस्वामी'' था। अधिकारी ने कहा-सुनवाई 27 जनवरी को तय थी। गोस्वामी को खुद पेश होने की ज़रूरत नहीं थी और उन्होंने अपने घर से ही मामला सुलझा लिया, जबकि उनके दो भाई-बहन एक लोकल स्कूल में सुनवाई में शामिल हुए। मालूम हो कि तेज़ गेंदबाज़ गोस्वामी ने भारत के लिए 12 टेस्ट, 204 एक दिवसीय और 68 टी मैच खेले। इधर, एसआईआर मामले पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई, जिसमें तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर एक नेशनल स्पोर्ट्स आइकॉन को निशाना बनाने का आरोप लगाया। यह याद करते हुए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2017 में गोस्वामी को ''भारत का गौरव'' कहा था, टीएमसी ने एक एक्स पोस्ट में कहा-उसी आइकॉन को अब यह साबित करने के लिए घसीटा जा रहा है कि वह भारतीय भी हैं या नहीं, उनके पिता के नाम में एक छोटी सी गड़बड़ी के लिए। पार्टी ने कहा-फोटो खिंचवाने के लिए हमारे हीरो का इस्तेमाल करो, फिर उन्हें बेइज़्ज़त करो, शक करो और सरकार की तरफ से बेइज़्ज़ती करवाओ। उन्होंने कहा कि ''जो पार्टी झूलन गोस्वामी की नागरिकता पर शक करती है, उसने सारी नैतिक ताकत खो दी है।''

मनोरंजन

नसीब का मशहूर गाना 'जॉन जानी जनार्दन'

- हिंदी सिनेमा के इस गाने को फिल्माने में लगे थे कुल 7 दिन
- 6.28 मिनट के गीत पर एक साथ थिरके थे 13 स्टार्स

निज संवाददाता : हिंदी सिनेमा में गाने अक्सर फिल्मों से भी ज्यादा मशहूर हो जाते हैं। एक खास 6.28 मिनट का गाना इसलिए मशहूर है क्योंकि इसमें कई बड़े और छोटे सितारे एक साथ नजर आते हैं। इसे और भी खास बात यह बनाती है कि इसे शूट करने में पूरे सात दिन लगे, जबकि आम गाने एक-दो दिन में पूरे हो जाते हैं। इस गाने के लिए एनर्जी, भव्यता और तालमेल की जरूरत थी, वही इसे बॉलीवुड के इतिहास में यादगार बना देती है। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कौन सा गाना है? यहां जिस गाने की बात हो रही है, वह 1981 में आई फिल्म नसीब का मशहूर गाना जॉन जानी जनार्दन है। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, शत्रुघ्न सिन्हा, रीना रॉय, ऋषि कपूर और कादर खान थे। मनमोहन देसाई निर्देशित इस गाने ने बॉलीवुड में एक नया रिकॉर्ड बनाया, जिसमें राज कपूर, धर्मेंद्र, वहीदा रहमान और शम्मी कपूर जैसे सितारों के साथ-साथ कई युवा कलाकार भी शामिल थे। इस गाने की शूटिंग में पूरा एक हफ्ता लगा, जो बॉलीवुड की भव्यता और कलाकारों व क्रू की लगन को दिखाता है। यह गाना आज भी फैंस के बीच एक क्लासिक सॉन्ग बना हुआ है।नसीब का गाना जॉन जानी जनार्दनजॉन जानी जनार्दन का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था, जबकि गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे।

दिग्गज गायक मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज से इस गाने को धुन दी, जो सितारों से सजे ट्रैक में चार चांद लगा देते हैं। अच्छी गायकी, मनमोहक बोल और इतने सारे बॉलीवुड स्टार्स की दमदार प्रेजेंस ने इस गाने को रातोंरात हिट बना दिया। कई सालों से यह गाना संगीत के लिए एक मिसाल बन गया है, और बाद की फिल्मों में इसी तरह के गानों को आजमाया गया है।फिल्म नसीब दोस्ती, विश्वासघात और बदले की कहानी बयां करती है, जिसका बैकग्राउंड ग्लैमर से भरपूर है। कहानी चार दोस्तों के इर्द-गिर्द घूमती है: नामदेव (प्राण) और उसके साथी दामू (अमजद खान), रघु (कादर खान) और जग्गी (जगदीश राज)। एक लॉटरी टिकट विश्वासघात को जन्म देता है, जिसके चलते हत्या और झूठे आरोप लगते हैं। नामदेव को मृत मान लिया जाता है, लेकिन वह जिंदा बच जाता है, जबकि उसका बेटा जॉनी (अमिताभ बच्चन) अनजाने में धोखेबाजों में से एक के बेटे से दोस्ती कर लेता है। बॉलीवुड स्टार्स को गिनते थक जाएंगेजॉन जानी जनार्दन गाने में बॉलीवुड स्टार्स की इतनी बड़ी संख्या देखकर आप दंग रह जाएंगे। अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ-साथ धर्मेंद्र, राज कपूर, वहीदा रहमान, रणधीर कपूर, बिंदू, प्रेम चोपड़ा, राजेश खन्ना, शर्मिला टैगोर, शम्मी कपूर और राकेश रोशन ने भी कैमियो रोल किया था। यहां तक कि जूनियर कलाकारों ने भी इसमें रंग भरा था।

मनमोहन देसाई ने सात दिनों में कोरियोग्राफी, कैमरा वर्क और सारी चीजें करके इस शूट को खत्म किया, जिसके बाद एक ऐसा गाना तैयार हुआ जो न केवल संगीत बल्कि उस दौर के पूरे बॉलीवुड को एक ही फ्रेम में समेटे हुए था। शाहरुख खान की फिल्म में भी फॉलो हुआ ये कॉन्सेप्टउनके गाने ने बाद की बॉलीवुड फिल्मों में इसी तरह का कॉन्सेप्ट दिया। इसका उदाहरण शाहरुख खान की 2007 में आई फिल्म ओम शांति ओम का गाना दीवानगी दीवानगी है। इस गाने में सलमान खान, सैफ अली खान, गोविंदा, मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, जायद खान, रानी मुखर्जी, काजोल, करिश्मा कपूर और कई एक्टर्स एक साथ आए थे। 1981 की क्लासिक फिल्म की तरह, इसमें भी कई कलाकारों को एक साथ कैमरे में कैद किया गया था। अब बड़े पैमाने पर कैमियो से भरे गानों का चलन बॉलीवुड की पहचान बन गया है।

'बॉर्डर 2' ने कमाए 300 करोड़

निज संवाददाता : सनी देओल की 'बॉर्डर 2' ने अबतक दुनियाभर से 300 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है। जबकि, 8 दिन पहले आई फिल्म अब अपने दूसरे वीकेंड पर पहुंच गई है। जिससे मेकर्स की उम्मीद भी काफी ज्यादा होगी। खैर, सनी देओल के खाते में इस समय कई बड़ी फिल्में हैं। जिसमें से एक पर हाल ही में अपडेट आया था, जिसमें वो फरहान अख्तर और एक्सेल एंटरटेनमेंट के साथ हाथ मिला रहे हैं। इधर 'बॉर्डर 2' का तूफान थमा भी नहीं है और कहा जा रहा है कि वो एक 30 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल लाने की तैयारी में हैं। जिसके लिए उनके ही फेवरेट डायरेक्टर मनाली पहुंच गए हैं। हालांकि, फैन्स इस बात से निराश हैं कि अबतक 'लाहौर 1947' का काम पूरी तरह से अटका हुआ है। सनी देओल की जिस फिल्म के सीक्वल की बात हो रही है, उसका पहला पार्ट 1996 में रिलीज हुआ था। फिल्म में सनी देओल के साथ मीनाक्षी शेषाद्रि, अमरीश पुरी और डैनी डेन्जोंगपा ने काम किया था। फिल्म का नाम है- घातक, जिसका बजट 6 करोड़ रुपये था। साथ ही फिल्म ने 32.7 करोड़ का बिजनेस किया था। जो भारत में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली पिक्चर थी। वहीं ग्लोबल मार्केट पर दूसरे नंबर पर रही थी। अब फिल्म के पार्ट 2 पर काम हो, इसके लिए राजकुमार संतोषी मनाली गए हैं।

'दुबई, रेडी फॉर ए सरप्राइज़'

- अनुष्का शर्मा और विराट कोहली की फिल्म में मिलते हैं दुबई के कई रंग और खूबसूरती

निज संवाददाता : दुबई डिपार्टमेंट ऑफ़ इकोनॉमी एंड टूरिज़्म (डीईटी) का हिस्सा, दुबई कॉर्पोरेशन फ़ॉर टूरिज़्म एंड कॉमर्स मार्केटिंग (विज़िट दुबई) ने 'दुबई, रेडी फ़ॉर अ सरप्राइज़' सीरीज़ की लेटेस्ट फ़िल्म लॉन्च की है, जिसमें भारत के पावर कपल अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नज़र आ रहे हैं। दुबई की सर्दियों को केंद्र में रखते हुए, यह फ़िल्म इस मूल विचार पर आधारित है कि यह शहर पहली बार आने वाले और बार-बार लौटने वाले दोनों तरह के पर्यटकों को लगातार चौंकाता रहता है और हर बार कुछ नया पेश करता है। इस बार कहानी में अनुष्का, विराट को सरप्राइज़ करती हुई दिखाई देती हैं।

दुबई के साथ जारी अपने डेस्टिनेशन पार्टनरशिप के तहत, यह नया चैप्टर पिछली फ़िल्म की सफलता को आगे बढ़ाता है और दर्शकों को अनुष्का द्वारा योजनाबद्ध एक दिनभर के सोच-समझकर रचे गए सरप्राइज के साथ इस जोड़े की यात्रा पर ले जाता है। यह फ़िल्म दुबई की गहराई, विविधता और सुविधाओं को उजागर करती है, जो इसे भारतीय यात्रियों के लिए एक सहज और पसंदीदा विकल्प बनाती हैं।

दुबई के जीवंत विंटर सीज़न के दौरान लॉन्च की गई यह फ़िल्म शहर के खूबसूरत सिटीस्केप और विशाल आउटडोर लोकेशन्स को बेहद खूबसूरती से कैद करती है, शांत रेगिस्तानी ठिकानों से लेकर धूप से नहाए बीचफ्रंट पलों तक। यह दर्शाती है कि कैसे दुबई यात्रियों को प्रकृति और शहरदो अलग-अलग तरह की छुट्टियों का अनुभव, एक ही ठहराव में, कुछ ही पलों के अंतर पर, प्रदान करता है। फ़िल्म का समापन अनुष्का की एक हल्की-सी झलक के साथ होता है, जिसमें वह संकेत देती हैं कि गर्मियों के मौसम में नज़ारा कितना शानदार हो सकता है। यह दुबई को हर मौसम के लिए एक बेहतरीन शहर के रूप में मज़बूती से स्थापित करता है।

स्वामी मोहता पब्लिशिंग हाउस के लिए, प्रकाशक, मुद्रक : अजय कुमार मोहता द्वारा अरिहंत मुद्रा, 61, सूर्यसेन स्ट्रीट, कोलकाता-700009 से मुद्रित एवं प्रकाशित। **संपादकीय कार्यालय :** 10, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद सरणी, (क्लाइब रो), 5बी मंजिल, रूम नं. 9, कोलकाता-700001, **स्थानीय कार्यालय :** 28-5 कन्वेंट रोड, मौलाली, कोलकाता-700014। **संपादक : अजय कुमार मोहता,** मो. 9830045693, E-mail-gambheersamachar@gmail.com. Website. www.gambheersamachar.in (प्रकाशित रचनाओं के चयन, संपादन हेतु पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी, सभी कानूनी विवाद के लिए कोलकाता न्याय क्षेत्र)